केंद्र और राज्य शासन से विज्ञापन के लिए अनुमोदित

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

17 वर्षों से निरंतर....

Website:- www.malwaherald.com

RNI No. MPHIN/2010/33238
dainikmalwaherald@yahoo.com
malwaherald@gmail.com

मालवा हेराल्ड

वर्ष : 17 अंक : 27 | उज्जैन, मंगलवार 07 जुलाई 2026 | पृष्ठ-8 | मूल्य-1 रुपए

महाकालेश्वर जी का संध्या काल आरती श्रृंगार दर्शन

सुविचार

अपेक्षाएं जहाँ खत्म होती हैं, सुकून वहीं से शुरू होता है...

न्यूज ब्रीफ

सलमान खान के ब्रेसलेट से लेकर लॉरेंस बिश्नोई विवाद तक, फिल्म काला हिरण पर बड़ी बहस; HC ने निजी अधिकारों पर घेरा

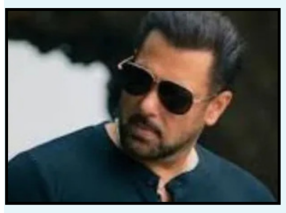

नई दिल्ली/ जीएनएस। क्या किसी अभिनेता के व्यक्तित्व अधिकार (पर्सनैलिटी राइट्स) का दायरा इतना व्यापक हो सकता है कि किसी फिल्म के टीजर, प्रचार सामग्री या प्रेरणा पर भी रोक लगाई जा सके। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता सलमान खान की याचिका पर सुनवाई के दौरान यही अहम सवाल उठाया। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट करना होगा कि निजी अधिकारों की सीमा आखिर कहां तक है। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की एकल पीठ सलमान खान की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने फिल्म काला हिरण- द बैटल फॉर लेगेसी की रिलीज और उसके टीजर पर रोक लगाने की मांग की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने सलमान खान की ओर से पेश अधिवक्ता से पूछा कि निजी अधिकारों को आखिर कितनी दूर तक बढ़ाया जा सकता है। अदालत ने कहा कि केवल यह दावा पर्याप्त नहीं होगा कि फिल्म किसी व्यक्ति से प्रेरित है या उसमें उससे मिलते-जुलते कुछ तत्व दिखाई देते हैं। सलमान खान का दावा है कि फिल्म उनके वर्ष 1998 के काला हिरण शिकार मामले और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ विवाद से प्रेरित है। उनका आरोप है कि निर्माताओं ने उनकी अनुमति के बिना उनकी सार्वजनिक छवि और व्यक्तित्व का व्यावसायिक लाभ उठाने की कोशिश की है। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि फिल्म के निर्देशक ने कई साक्षात्कारों में स्वीकार किया है कि फिल्म सलमान खान से प्रेरित है। साथ ही, फिल्म में अभिनेता की पहचान से जुड़े कुछ विशेष तत्व, जैसे उनका प्रसिद्ध ब्रेसलेट, भी दिखाए गए हैं। इसलिए यह उनके निजी अधिकारों का उल्लंघन है।

6695 करोड़ रुपये का मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे लिंक एक मानसून भी नहीं झेल पाया

मुंबई/ जीएनएस। मुंबई में बीते दिनों तपती गर्मी से बेहाल लोग सिर्फ एक ही दुआ कर रहे थे कि जैसे भी हो, जल्द से जल्द मानसून दस्तक दे ताकि इस झुलसाती तपिश से राहत मिले। कुदरत ने दुआ सुनी तो सही, लेकिन जब आर्थिक राजधानी में देरी से पहुंचे मानसून ने रफ्तार पकड़ी, तो राहत पल भर में आफत में बदल गई। हाल ये है कि आज पूरा महाराष्ट्र जलमग्न है और इसी आसमानी आफत ने मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे को लेकर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए। इस बात को ऐसे समझिए कि करोड़ों की लागत, चमचमाती सड़कें और देश के सबसे आधुनिक रास्तों में शुमार होने का दम भरने वाले मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे पहली मानसून भी नहीं झेल पाया और लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन ने इस एक्सप्रेसवे लिंक के चमचमाते दावों की पोल खोलकर रख दी। सोमवार तड़के करीब 3ः30 बजे मिसिंग लिंक टनल के पास हुए भारी भूस्खलन और लगातार आसमान से बरसते बारिश के चलते प्रशासन को मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे और पुराना हाईवे, दोनों ही तरफ से पूरी तरह बंद करना पड़ा। अब इसको लेकर सवाल इसलिए खड़े होने लगे कि जो प्रोजेक्ट कल तक विकास की मिसाल था, वह आज एक ही झटके में राहगीरों के लिए मुसीबत कैसे बन गया? हैरानी की बात यह है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महज नौ हफ्ते पहले, 1 मई 2026 को ही इस फ्लैगशिप स्ट्रेच का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के दो महीने के भीतर ही इस 6695 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर पहले गड्ढे उभरे और अब इस भूस्खलन ने सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम के मुताबिक, खालापूर टोल प्लाजा के पास मलबे को साफ करने में 3 से 5 घंटे का समय लगा। भारी मशक्कत और पानी का स्तर कम होने के बाद दोपहर तक रास्ता खोला जा सका, लेकिन गाड़ियों की रफ्तार बेहद धीमी रही। बता दें कि सड़क के साथ-साथ रेल यातायात पर भी आफत आई।

सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र भोपाल की विकास यात्रा में होगा मंदिर के समान : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

सतगढ़ी क्षेत्र भोपाल के आस-पास नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम

भोपाल/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर भोपाल को सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क और कन्वेंशन सेंटर की बड़ी सौगात मिली है। यह इंडस्ट्रियल पार्क देश के पहले उद्योग मंत्री डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में 15 हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। सतगढ़ी क्षेत्र औद्योगिक विकास की दिशा में एक मंदिर के समान होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम जो कहते हैं, करके दिखाते हैं। प्रदेश में विकसित हो रहे औद्योगिक क्षेत्र हमारे किसानों के लिए भी समृद्धि का द्वार खोलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। गारमेंट इंडस्ट्री से कपास उत्पादक किसानों को लाभ मिलेगा। हमारी सरकार खेत से कारखाने और उद्योग को बाजार से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी अलग पहचान बना रहा है। उन्होंने गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार प्रदेश के हर वर्ग के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर सोमवार को भोपाल के कोलार क्षेत्र स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक क्षेत्र का भूमिपूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश - एक विधान - एक निशान - एक प्रधान की बात कही थी। उनके इस संकल्प को साकार करने के लिए राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। समाज के हर वर्ग के लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि यूसीसी मध्यप्रदेश में लागू होगा। इसके लिए कमेटी ने सभी धर्म-समुदाय के सुझाव लिए गए, जिससे किसी के साथ भेदभाव न हो। देश के बड़े राज्यों में, मध्यप्रदेश समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य होगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क से राजाभोज विमानतल की दूरी महज 25 किलोमीटर है। रानी कमलापति स्टेशन भी मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भोपाल का वेस्टर्न बायपास भी यहीं से गुजरेगा। सतगढ़ी के 25 एकड़ क्षेत्र में 10 हजार क्षमता वाला एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर भी बनेगा। यह प्रदेश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। मध्यप्रदेश अपने औद्योगिक विकास और पारदर्शी व्यवस्था के साथ तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। सागर ग्रुप के श्री सुधीर अग्रवाल सतगढ़ी में 100 करोड़ का निवेश करेंगे। भोपाल प्राकृतिक सुंदरता और झील-तालाबों की नगरी है, लेकिन अब यह स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क भी राजधानी की पहचान बनेगा। अनेक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भोपाल औद्योगिक नगरी के रूप में नई पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यहां से प्रदेश के विकास का नया सूर्योदय हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक अंचल में देश-दुनिया के निवेशक औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर रहे हैं। पिछले रविवार को शिवपुरी में 2500 करोड़ लागत से रक्षा क्षेत्र की बड़ी औद्योगिक ईकाई का भूमि-पूजन किया है। यहां बनने वाली मिसाइलों की क्षमता 1000 किलोमीटर की होगी। इससे पहले मुरैना को सोलर सेक्टर की बड़ी सौगात दी है। रोजगार आधारित उद्योगों के लिए गुना में 2 हजार करोड़ रुपये का सीमेंट प्लांट भी बनाया जा रहा है। विकसित भारत ॠ2047 के संकल्प की पूर्ति में मध्यप्रदेश विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भोपाल में पहली बार जीआईएस जैसे बड़ा आयोजन संपन्न हुआ, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का

मुंबई में मूसलाधार बारिश, नासिक में मंगलवार को बादल फटने की आशंका; हाई अलर्ट पर प्रशासन

मुंबई/ जीएनएस। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में पिछले चार दिनों से जारी मूसलाधार बारिश अब जानलेवा साबित होने लगी है। लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण पूर्वी उपनगर मानखुर्द में एक तीन मंजिला चाल अचानक ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

इस हादसे में मलबे के नीचे दबकर छह लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में पूरे महाराष्ट्र में बारिश के कारण विभिन्न घटनाओं में 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने मंगलवार को नासिक में बादल फटने और 300 मिमी. तक बरसात होने की आशंका भी जताई है। मानखुर्द में इमारत ढहने से 6 लोगों की मौत हुई

मानखुर्द में रविवार देर शाम तीन मंजिला चाल ढहने के बाद घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए थे।

इस दुर्घटना में छह लोग मारे गए हैं। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और दमकल विभाग ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया था।

सोमवार सुबह आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्यों का निरीक्षण किया है।

दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए मुख्यमंत्री ने पांच-पांच रुपए मुआवजे की घोषणा की है। इस भीषण बारिश ने मायानगरी मुंबई की रफ्तार पर तो पूरी तरह ब्रेक लगा ही दिया है।

भारी बारिश का सबसे बड़ा असर मुंबई और पुणे के बीच के संपर्क पर पड़ा है, जिससे दोनों शहरों के बीच रेल और सड़क मार्ग बाधित हो गए हैं। कर्जत के पास पहाड़ी खिसकने (भूस्खलन) से रेलवे ट्रैक पर भारी मलबा आ गया है।

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने मुंबई-पुणे के बीच चलने वाली सभी रेल सेवाओं को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है।

नीरव मोदी को बड़ा झटकाः हार गया आखिरी कानूनी लड़ाई, कभी भी हो सकता है प्रत्यर्पण

नई दिल्ली/ जीएनएस। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय (श्वष्ट॥क्र) से करारा झटका लगा है। वह अपनी आखिरी कानूनी लड़ाई भी हार गया है। अंतिम कानूनी याचिका खारिज होने के बाद अब उसके प्रत्यर्पण की राह में कोई बाधा नहीं बची है। रिपोर्ट है कि ब्रिटेन सरकार ने नीरव मोदी को भारत सौंपने की प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी है और भारतीय अधिकारियों के साथ राजनयिक समन्वय चल रहा है। न्यूज18 की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटेन की सभी घरेलू अदालतों में अपीलें समाप्त होने के बाद नीरव मोदी ने अप्रैल 2026 में श्वष्ट॥क्र में अंतिम याचिका दायर की थी। अदालत ने उसे कोई अंतरिम राहत या रोक नहीं दी। इसके साथ ही प्रत्यर्पण को चुनौती देने का आखिरी कानूनी विकल्प भी खत्म हो गया है। ऐसे में कभी भी उसका प्रत्यर्पण हो सकता है।

नीरव मोदी मार्च 2019 से लंदन की एचएमपी वैंड्सवर्थ जेल में बंद है। इस दौरान उसने ब्रिटिश अदालतों में जमानत और प्रत्यर्पण रोकने के लिए कई याचिकाएं दायर की, लेकिन हर बार असफल रहा।

बस स्टॉप पर दिनदहाड़े युवक ने 17 साल की लड़की को मारा चाक़ू, हमलावर की तलाश में जुटी पुलिस

मंगलुरु/ जीएनएस। कर्नाटक के मंग्लुरु से एक खौफनाक वरदार की खबर सामने आ रही है। यहां सोमवार को एक युवक ने 17 साल की छात्रा पर चाक़ू से हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब छात्रा कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पट इंतजार कर रही थी।

मंगलुरु में छात्रा पर चाकू से हमला- हमला बंटवाल ग्रामीण पुलिस स्टेशन इलाके के मोंटीमारू पडपू बस स्टॉप पर हुआ। आरोपी की पहचान मोंटीमारू पडपू के रहने वाले 28 साल के जव्वार के तौर पर हुई है, जो बस स्टॉप के पास ही किराने की दुकान चलाता है। पुलिस ने बताया लड़की कॉलेज जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी, तभी आरोपी ने कथित तौर पर उस पर चाकू से हमला कर दिया।

हमले के बाद बस स्टॉप पर मौजूद दूसरे यात्रियों ने तुरंत शोर मचाया, जिससे आरोपी मौके से भाग गया। हमले में घायल छात्रा को तुरंत मंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है।

बंटवाल ग्रामीण पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया और बाद में अस्पताल में पीड़िता का बयान दर्ज किया। हमले के पीछे की असली वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। फरार आरोपी को खोजने और गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक स्पेशल टीम बनाई गई है।

कुश्ती महासंघ दो हफ्ते में ले निर्णय, विनेश फोगाट के कारण बताओ नोटिस पर दिल्ली हाई कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली/ जीएनएस। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) को पहलवान विनेश फोगाट को जारी कारण बताओ नोटिस पर दो सप्ताह के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि निर्णय से पहले विनेश फोगाट को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जाए।

न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की एकल पीठ ने यह आदेश विनेश फोगाट की याचिका का निस्तारण करते हुए दिया। याचिका में उन्होंने कारण बताओ नोटिस के अलावा डब्ल्यूएफआई की चयन नीति और एशियाई खेलों के चयन ट्रायल से संबंधित सर्कुलर को भी चुनौती दी थी। सुनवाई के दौरान डब्ल्यूएफआई की ओर से अदालत को बताया गया कि एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में भागीदारी से जुड़ी विनेश फोगाट की शिकायत अब निरर्थक हो चुकी है, क्योंकि अदालत के पूर्व आदेश के बाद उन्हें ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी गई थी। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि मौजूदा याचिका का निस्तारण किया जा सकता है और यदि चयन नीति या अन्य मुद्दों को चुनौती देनी है तो उसके लिए अलग से नई याचिका दायर करनी होगी।

विनेश फोगाट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि मामला केवल उनके चयन तक सीमित नहीं है, बल्कि डब्ल्यूएफआई की चयन नीति से जुड़े व्यापक प्रश्न भी उठाता है। हालांकि, अदालत ने इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि इस संबंध में अलग याचिका दाखिल की जा सकती है।

एआई-रेडी और ग्रीन डेटा हब बनेगा उत्तर प्रदेश, कैबिनेट बैठक में नई नीति पर मुहर

लखनऊ/ जीएनएस। उत्तर प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक अत्याधुनिक और टिकाऊ तकनीकी महाशक्ति बनाने की दिशा में योगी सरकार ने सोमवार को एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बहुप्रतीक्षित उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति-2026 को हरी झंडी दे दी गई। इस महत्वाकांक्षी नीति का मुख्य उद्देश्य यूपी को देश का पहला ग्रीन, एआई-रेडी और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी डेटा सेंटर हब बनाना है। इस नई नीति के जरिए सरकार ने प्रदेश में 2 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने और 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भारी-भरकम निवेश आकर्षित करने का रोडमैप तैयार किया है। इसके साथ ही, इस पूरी योजना से प्रदेश के करीब 50 हजार युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना जताई जा रही है। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि पुरानी नीति के 27 जनवरी 2026 को समाप्त होने के बाद, बदलते तकनीकी परिदृश्य को देखते हुए यह नई और उन्नत नीति लाई गई है। इस बार सरकार का विशेष ध्यान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरण संरक्षण पर है।

इस नीति को मंजूरी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में एक वर्ल्ड-क्लास डेटा सेंटर इकोसिस्टम खड़ा होगा। डेटा सेंटर्स के आने से उनके आसपास सूचना प्रौद्योगिकी और आईटीईएस सेक्टर की अन्य कंपनियों का भी जमावड़ा लगेगा, जिससे रोजगार के अभूतपूर्व अवसर सृजित होंगे।

पिछली नीति की सफलता के बाद अगला बड़ा कदम- मंत्री सुनील शर्मा ने रेखांकित किया कि योगी सरकार की सुनियोजित नीतियों के कारण ही प्रदेश में तकनीकी निवेश को रफ्तार मिली है। जनवरी 2021 में लागू हुई और नवंबर 2022 में संशोधित हुई पिछली डेटा सेंटर नीति के बेहद ठोस परिणाम सामने आए हैं।

पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्राः रक्षा संबंधों समेत किन-किन मुद्दों पर होगी बात?

नई दिल्ली/ जीएनएस। पीएम नरेन्द्र मोदी की तीन दिवसीय इंडोनेशिया यात्रा से भारत और इंडोनेशिया के द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को एक नई दिशा प्रदान करेगी। इस यात्रा के दौरान दोनों देश डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, भुगतान प्रणाली, रक्षा सहयोग को बढ़ा कर अपनी साझेदारी को और गहरा करेंगे।

इस यात्रा के दौरान भारत के यूपीआई और इंडोनेशिया के क्यूरिस (क्यूआरआईएस) के बीच डिजिटल भुगतान लिंकेज का समझौता होगा। इससे बाली और अन्य इंडोनेशियाई पर्यटन स्थल पर जाने वाले लाखों भारतीय पर्यटकों के लिए भुगतान बेहद आसान, तेज और सस्ता हो जाएगा। इंडोनेशिया से कारोबार करने वाले भारतीय व्यवसायियों को भी लाभ होगा।

विदेश मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि इंडोनेशिया धीरे धीरे भारत के कई विकास कार्यक्रमों से प्रेरणा ले रहा है और उनका अनुकरण करना चाहता है। इस बारे में भारत सरकार भी पूरी मदद को तैयार है। इंडोनेशिया का ओपन नेटवर्क (आईओएन) भारत के ओएनडीसी माडल से प्रेरित है।

आईओएन का पहला लाइव ट्रांजेक्शन- 7 जुलाई को पीएम मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांटो के शिखर सम्मेलन के दौरान आईओएन का पहला लाइव ट्रांजेक्शन करने की तैयारी है। यह 6.5 करोड़ से ज्यादा सूक्ष्म, छोटे व मझोले स्तर के उद्यमियों के लिए बहुत ही सहूलियत वाला और कम लागत वाला डिजिटल मार्केटप्लेस तैयार करेगा।

सनद रहे कि भारत की आधार, यूपीआई, डिजिलाकर व ई-केवाइसी से प्रेरिसत हो कर इंडोनेशिया सरकार ने महत्वाकांक्षी डिजिटल नुसंतरा पहल की शुरुआत की है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुशासन विजन को साकार करने की दिशा में इंदौर जिला प्रशासन की अभिनव पहल

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में विकसित चैटबॉट बना नागरिकों का डिजिटल सहायक

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सुशासन, पारदर्शिता एवं नागरिक-केंद्रित प्रशासन की सोच को साकार करते हुए इंदौर जिला प्रशासन ने आम नागरिकों को त्वरित एवं सरल शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक अत्याधुनिक व्हाट्सएप आधारित चैटबॉट विकसित किया है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा के निर्देशन में तैयार इस अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म को नागरिकों का उत्साहजनक प्रतिसाद मिल रहा है।

चैटबॉट के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपने मोबाइल से विभिन्न शासकीय सेवाओं की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तथा निर्धारित समय-सीमा में ऑनलाइन आवेदन की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। इससे कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर कम हुए हैं और सेवाओं का वितरण अधिक पारदर्शी, तेज एवं प्रभावी बना है। इस चैट बॉट का नम्?बर - 9407035437 है।

पिछले 15 दिनों के आँकड़े इस पहल की सफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। इस अवधि में 2,910 नागरिकों ने चैटबॉट का उपयोग किया, जिनमें से 2,880 सक्रिय उपयोगकर्ता रहे। चैटबॉट पर 29,269 संदेश प्राप्त हुए तथा विभिन्न शासकीय सेवाओं से संबंधित 2,949 सेवा विवरण देखे गए। 2,551 नागरिकों ने सिटिजन सर्विसेज मेन्यू का उपयोग किया और 2,532 बार विभिन्न सेवाओं की जानकारी देखी गई।

चैटबॉट में उपलब्ध कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सहायक का भी नागरिकों ने व्यापक उपयोग किया। 1,306 नागरिकों ने एआई असिस्टेंट का उपयोग किया तथा 1,173 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त नागरिकों द्वारा दिए गए सुझाव एवं प्रश्नों के आधार पर चैटबॉट को लगातार और अधिक उपयोगी बनाया जा रहा है।

प्रारंभिक चरण में चैटबॉट के माध्यम से आय, जाति, मूल निवासी, जन्म एवं मृत्यु 01 वर्ष के पश्?चात पंजीयन के लिये प्रमाण-पत्र आधार अपडेट सहित विभिन्न विभागों की अनेक जनसेवा संबंधी जानकारी /सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। नागरिक अपने आवेदन की स्थिति भी ऑनलाइन देख सकते हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनी है। कलेक्टर श्री शिवम वर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य तकनीक के माध्यम से शासन की सेवाओं को आम नागरिकों तक सहज और त्वरित रूप से पहुँचाना है। आने वाले समय में इस चैटबॉट में और अधिक विभागों तथा सेवाओं को जोड़ा जाएगा, ताकि नागरिकों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अधिकतम शासकीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।

यह पहल इंदौर जिला प्रशासन द्वारा डिजिटल गवर्नेंस और सुशासन की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद को और अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बना रहा है।

होर्डिंग मुक्त और सुंदर इंदौर बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर कांग्रेस ने इंदौर को होर्डिंग मुक्त और अधिक सुंदर बनाने की मांग को लेकर सोमवार को नगर निगम आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया और अपर आयुक्त मनोज कुमार पाठक को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने शहर में राजनीतिक दलों और विभिन्न आयोजनों के नाम पर लगाए जा रहे होर्डिंग्स पर रोक लगाने तथा नगर निगम की पूर्व नीति को सख्ती से लागू करने की मांग की।

शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे और नेता प्रतिपक्ष सोनीला मिमरोट भाटिया ने कहा कि नेताओं के जन्मदिन और अन्य कार्यक्रमों के अवसर पर शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े पैमाने पर होर्डिंग लगाए जाते हैं, जिससे इंदौर की सुंदरता प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम द्वारा ऐसी नीति लागू थी, जिसके तहत अवैध होर्डिंग्स को तत्काल हटाया जाता था। शहर की स्वच्छ और सुंदर छवि बनाए रखने के लिए उसी नीति का निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से पालन किया जाना चाहिए।

कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि नगर निगम शहर को होर्डिंग मुक्त बनाने के लिए ठोस नीति अपनाए और उसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अपर आयुक्त आकाश सिंह के स्तर पर इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और शहर को होर्डिंग मुक्त बनाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो कांग्रेस पार्टी आगे भी निगम कार्यालय का घेराव कर आंदोलन जारी रखेगी।

आकाशीय बिजली/ वज्रपात की आपदाओं से बचाव हेतु एडवायजरी जारी, विभागों को सौंपे दायित्व

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आकाशीय बिजली/ वज्रपात की आपदाओं से बचाव हेतु एडवाइजरी जारी करते हुए विभागीय तथा जिला स्तर पर पूर्व - तैयारी के सभी आवश्यक कदम उठाए जाने हेतु विभिन्न विभागों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

विगत वर्षो के दौरान, प्रदेश में आकाशीय बिजली / वज्रपात के कारण व्यापक स्तर पर जान- माल का नुकसान हुआ है। अधिकांश घटनाओं में खेतों अथवा खुले क्षेत्रों में काम करने वाले लोग प्रभावित हुए है। व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता, मैदानी स्तर तक चेतावनी प्रसारण की व्यवस्था तथा स्थानीय स्तर पर पूर्व तैयारी के उपायों द्वारा इन घटनाओं में जान माल के नुकसान को रोका जा सकता है।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण - चेतावनी अवधि के दौरान जिला कमांड, कण्ट्रोल एवं कोआर्डिनेशन सेंटर को 24×7 कार्यरत रखा जावे तथा DCCC का समन्वय पुलिस कण्ट्रोल रूम तथा स्वास्थ्य सेवा कण्ट्रोल रूम, नगरीय निकाय कण्ट्रोल रूम आदि से सुनिश्चित की जाए। जिले के समस्त फील्ड स्टाफ को Ministry of Earth Sciences, Government of India द्वारा विकसित मोबाइल एप "DAMINI " को अपने मोबाइल पर स्थापित करनें के निर्देश दिए जाएँ, ताकि उन्हें उस क्षेत्र में आकाशीय बिजली / वज्रपात की संभावना की जानकारी 24 घंटे प्राप्त हो। जन समुदाय को भी "DAMINI" मोबाइल एप को डाउनलोड करने की सलाह विभिन्न माध्यमों से दी जाए। जिला स्तर पर आकाशीय बिजली, तूफान, धूल भरी आंधी आदि प्राकृतिक आपदाओं के बचाव से संबन्धित जनजागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। जन-सामान्य को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव हेतु अपनाई जाने वाली सावधानियों से संबन्धित सुझाव का प्रचार प्रसार मीडिया के अन्य साधनों से करने की व्यवस्था की जाए।

इंदौर पुलिस की नई पहलः 5 थानों में शुरू हुई ECIT साइबर हेल्प डेस्क, साइबर फ्रॉड पीड़ितों को मिलेगा तत्काल सहयोग

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और पीड़ितों को थाना स्तर पर ही त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नई पहल की शुरुआत की है। शहर के चारों जोन के थाना राजेंद्र नगर, विजय नगर, भंवरकुआं, पलासिया तथा क्राइम ब्रांच में ECIT (E&pert Cyber Investigation Team) के अंतर्गत विशेष साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। इन हेल्प डेस्क का शुभारंभ पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने थाना पलासिया से किया। कार्यक्रम में अन्य संबंधित थाने वर्चुअल माध्यम से जुड़े।

इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध/मुख्यालय) आर.के. सिंह, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) मयंक अवस्थी, पुलिस उपायुक्त नरेंद्र सिंह रावत, अमन सिंह राठौड़, अभिषेक रंजन, सुनील कुमार मेहता सहित अन्य पुलिस अधिकारी, कर्मचारी एवं जैन दिवाकर स्कूल, डी फ्लाई और अक्सा इंटरनेशनल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर के विद्यार्थी उपस्थित रहे।

पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने पलासिया थाने में स्थापित श्ष्टढ्ढञ्ज साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि इन हेल्प डेस्क के माध्यम से साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों पर तत्काल और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, जिससे पीड़ितों को शुरुआती स्तर पर ही आवश्यक सहायता मिल सकेगी।

उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम जागरूकता है। इसी उद्देश्य से इंदौर पुलिस द्वारा सेफ क्लिक 2.0 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस कमिश्नर ने विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव के उपायों की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के कारण वे विभिन्न ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराधों से स्वयं को सुरक्षित रखने में सफल रहे।

इंदौर पुलिस का मानना है कि थाना स्तर पर शुरू की गई यह नई व्यवस्था न केवल साइबर अपराधों की शिकायतों के त्वरित निराकरण में सहायक होगी, बल्कि आम नागरिकों में डिजिटल सुरक्षा के प्रति विश्वास बढ़ाने के साथ-साथ साइबर अपराधों के प्रति व्यापक जनजागरूकता भी पैदा करेगी।

राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में है अग्रसर : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनसंघ के संस्थापक और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, श्रद्धेय डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर लालघाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पौधरोपण किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्मरण करते हुए कहा कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पूरे सम्मान के साथ मनाई जा रही है। डॉ. मुखर्जी के %एक देश-एक विधान-एक निशान-एक प्रधान% के संकल्प को साकार करने की दिशा में मध्यप्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार इसी माह समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में अग्रसर है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में भारत ने विश्व में बनाई विशेष पहचान -मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए विश्व में विशेष पहचान बनाई है। डॉ. मुखर्जी ने देश और समाज के सर्वांगीण विकास की कल्पना की। राज्य सरकार ने डॉ. मुखर्जी की जयंती के अवसर पर 15 दिवसीय जनकल्याण पखवाड़े की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गरीब, जरूरतमंद और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जा रहा है। राज्य सरकार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इस दिशा में रोजगार के अवसर सृजित होने से हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित हो पा रहा है।

हर क्षेत्र में तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है मध्यप्रदेश- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशानुसार बना दिल्ली में बना भारत मंडपम हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। डॉ. मुखर्जी की जयंती पर आज भोपाल के सतगढ़ी में मध्यप्रदेश के सबसे बडे कन्वेंशन सेंटर और सतगढ़ी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की आधारशिला रखी जा रही है। राज्य सरकार कुशाभाऊ ठाकरे सभागार के पास एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर तैयार कर रही है, जिसकी क्षमता 5 हजार सीट्स की रहेगी। सतगढ़ी में बनने वाले नए विशाल कन्वेंशन सेंटर में 10 हजार से अधिक व्यक्तियों की व्यवस्था है। भोपाल सबसे समृद्ध और सशक्त राजधानी बनने जा रहा है। हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तेजी से विकास करते हुए आगे बढ़ रहा है।

अब मध्यप्रदेश की धरती पर बनेंगे, रक्षा क्षेत्र के उपकरण, मिसाइल और हथियार- मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने रक्षा क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। अब रक्षा क्षेत्र के कई उपकरण, मिसाइल और हथियार मध्यप्रदेश की धरती पर बनेंगे। चंबल की धरती सालों से मां भारती की सेवा करने वाले वीर सैनिकों की भूमि रही है। अब यहां आधुनिक हथियार भी तैयार किए जाएंगे। यह मिसाइल एक हजार किलोमीटर तक दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने की क्षमता वाली होंगी। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण तथा सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, प्रदेश अध्यक्ष एवं वरिष्ठ विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, श्री रवीन्द्र यति, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में जुटेंः डॉ. के.पी. यादव

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर ग्रामीण द्वारा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर डॉ. अंबेडकर नगर (महू) स्थित उत्तम गार्डन में भव्य कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर किया।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा ने स्वागत भाषण में कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत में राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान राष्ट्रनायक थे। उनके विचार और जीवन आज भी प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।

मुख्य वक्ता मध्य प्रदेश राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष डॉ. के.पी. यादव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समर्पित रहा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि विचार और संगठन की शक्ति से संचालित होने वाली पार्टी है। सेवा, समर्पण और राष्ट्रहित की भावना ही भाजपा की पहचान है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे डॉ. मुखर्जी के विचारों को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण के कार्य में पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ जुटें।

पूर्व सांसद कृष्णमुरारी मोघे ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्श आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए भाजपा कार्यकर्ता समाज के अंतिम व्यक्ति तक केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं।

विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र की अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका जीवन देशभक्ति, साहस और त्याग का अनुपम उदाहरण है, जिससे प्रत्येक कार्यकर्ता को प्रेरणा लेकर समाज और राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए।

सम्मेलन में सांसद शंकर लालवानी, पूर्व विधायक जीतू जिराती, अंतरसिंह दरबार, भगवान परमार, देवराज सिंह परिहार, राधेश्याम यादव, ओम परसावदिया, डॉ. रीता उपमन्यु, कंचन सिंह चौहान, सतीश मालवीय, जय कोहली, सुभाष महोदय, मोहन सिंह कछावा, रामस्वरूप गेहलोत, अंतर दयाल, मुकेश जरिया, महेश यादव, विनोद जाट, संतोष पाटीदार, पवन सिंह पटेल, भरत आंजना, सुनील गेहलोत, पीयूष अग्रवाल, संजय मीणा, मुकेश पाटीदार, मनोज ठाकुर, किरण सूर्यवंशी, मुकेश पटेल, विनोद चंदानी, चंकी शर्मा, सुभाष पाटीदार सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री पुंजालाल निनामा ने किया, जबकि आभार रूपेश वाघमोड़े ने व्यक्त किया।

भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी की 125 वी जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

देपालपुर/ अंकित भोला परमार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं राष्ट्रीय एकता के सशक्त समर्थक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की 125 वी जयंती पर देपालपुर नगर के बेटमा नाका स्थित प्रतिमा पर विनम्र नमन कर पुष्पमाला अर्पित की। इस अवसर पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा, मंडल अध्यक्ष देवकरण दरबार, जिला मंत्री सत्यनारायण पटेल , अध्यक्ष प्रतिनिधि महेशपुरी गोस्वामी, उपाध्यक्ष गोपाल कटेसरिया ,पार्षदगण एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर माल्यार्पण, एमआर-4 सड़क का नाम उनके नाम पर होगा

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं देश की एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर रविवार को विजयनगर चौराहे स्थित उनकी प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट एवं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने माल्यार्पण कर राष्ट्र निर्माण में डॉ. मुखर्जी के योगदान का स्मरण किया। मंत्री तुलसीराम सिलावट और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता, सांस्कृतिक गौरव और जनसेवा के लिए समर्पित रहा। उनके आदर्श, विचार और राष्ट्रहित में किए गए कार्य आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं तथा उनके बताए मार्ग पर चलकर राष्ट्र निर्माण को नई दिशा दी जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमआर-4 मास्टर प्लान सड़क, जो शास्त्री ब्रिज के नीचे से बाणगंगा रेलवे क्रॉसिंग तक जाती है, का नामकरण डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किए जाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह निर्णय राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए डॉ. मुखर्जी के योगदान को सम्मान देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भी डॉ. मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को नमन करते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वक्ताओं ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया तथा उनका त्याग और बलिदान सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर विधायक रमेश मेंदोला, पूर्व महापौर कृष्ण मुरारी मोघे, भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, स्वास्थ्य प्रभारी अश्विनी शुक्ल, पार्षद कमल वाघेला सहित अन्य जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी, पार्षदगण एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

'स्वच्छ जल, समुचित उपचार - डायरिया से बचें हर बार' अभियान अंतर्गत ग्रामीणों को किया गया जागरूक

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 16 जून से 31 जुलाई 2026 तक संचालित स्वच्छ जल, समुचित उपचार - डायरिया से बचें हर बार अभियान के अंतर्गत आज 06 जुलाई 2026 को झाबुआ जिले के विभिन्न विकासखंडों में जनजागरूकता एवं स्वच्छता गतिविधियों का आयोजन किया गया।

अभियान के तहत विकासखंड झाबुआ एवं रामा के ग्राम वलोला, पारा एवं खरडू बड़ी में पेयजल स्त्रोतों के आसपास विशेष साफ-सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल के महत्व, जल जनित बीमारियों की रोकथाम, व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता तथा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं।

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीण महिलाओं के साथ संवाद कर उन्हें शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल के उपयोग, जल स्त्रोतों की स्वच्छता बनाए रखने तथा डायरिया एवं अन्य जल जनित बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उपस्थित ग्रामीणों को स्वच्छता एवं जल संरक्षण के प्रति जागरूक रहने तथा अपने गांवों को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने की सामूहिक शपथ भी दिलाई गई।

इस अवसर पर विकासखंड झाबुआ एवं रामा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर उपस्थित रहे तथा उन्होंने अभियान के उद्देश्यों एवं जनसहभागिता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए ग्रामीणों से स्वच्छता एवं जल संरक्षण गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

अभियान के अंतर्गत जिले में आगामी दिनों में भी विभिन्न ग्रामों में स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल एवं जल संरक्षण संबंधी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन निरंतर किया जाएगा।

राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए डॉ. मुखर्जी ने दिया सर्वोच्च बलिदानः संपतिया उइके

इंदौर/ हर्ष कुशवाहा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती वर्ष पर आयोजित संस्मरण पखवाड़ा के अंतर्गत मनमोहन मेहता ऑडिटोरियम, संगीत कला अकादमी, अटल खेल परिसर (स्कीम नंबर-78) में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके, पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार, नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, महापौर पुष्यमित्र भार्गव तथा विधायक रमेश मेंदोला, गोलू शुक्ला, महेंद्र हार्डिया और मधु वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने पूरे जीवन में कभी भी सिद्धांतों और विचारों से समझौता नहीं किया। उन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। नेहरू सरकार की नीतियों से असहमति होने पर उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर जनसंघ की स्थापना की। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हुए राष्ट्रसेवा कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के कौशल विकास तथा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पवन पाटीदार ने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने हमेशा राष्ट्रहित और अपनी विचारधारा के लिए संघर्ष किया। चाहे नेहरू-लियाकत समझौते का विरोध हो या कश्मीर में धारा-370 का मुद्दा, उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने बंगाल के विभाजन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कश्मीर में परमिट व्यवस्था के विरोध में आंदोलन कर राष्ट्र की एकता के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉ. मुखर्जी के सपनों का आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि आजादी के बाद देश की पहली सरकार में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी प्रशासनिक क्षमता और दूरदर्शिता के कारण उद्योग मंत्री बनाया गया। उन्होंने देश की पहली उद्योग नीति तैयार कर भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा दिखाई। भारी उद्योगों के साथ-साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की उनकी सोच आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से डॉ. मुखर्जी के संकल्पों को साकार कर रहे हैं।

नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता वर्षों से डॉ. मुखर्जी के राष्ट्रवाद के विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का सपना था कि देश में ÷एक निशान, एक विधान और एक प्रधान÷ हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद-370 हटाकर उनके ÷एक भारत-श्रेष्ठ भारत÷ के संकल्प को साकार करने का कार्य किया है।

कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने पौधारोपण किया तथा डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। सम्मेलन में अश्विनी शुक्ल, अमरदीप मौर्य, हरिनारायण यादव, अंजू माखीजा, मानसिंह यादव, अनंत पंवार, सुधीर कोल्हे, महेश कुकरेजा, राकेश शर्मा, वासुदेव पाटीदार, भारत पारख, भूपेंद्र सिंह केसरी, दीपेंद्र सिंह सोलंकी, दीप्ति हाड़ा, नेहा शर्मा, नारायण पालीवाल, सचिन बंसल आदी।

बच्चा यदि गलत काम करें तो उसका पक्ष ना लें, स्कूलों में बच्चों की उम्र के अनुसार अनुशासन हेतु सख्ती जरूरी होती है- शिक्षाविद् रमेशचन्द्र चन्द्रे

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शिक्षाविद् एवं सामाजिक चिंतक रमेशचन्द्र चन्द्रे ने कहा है कि आजकल तथाकथित शिक्षाविदों एवं अपने आपको बाल मनोविज्ञान का एक्सपर्ट समझने वाले तथा बाल संरक्षण संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों ने कुछ ऐसा माहौल बना दिया है कि स्कूलों में किसी भी प्रकार की कठोरता नहीं होना चाहिए तथा सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया ने भी स्कूलों के अनुशासन को लेकर तमाशा बनाने का धंधा कर लिया है।

नर्सरी कक्षाओं से लेकर पांचवी कक्षा के बच्चों पर वैसे भी सख्ती कम ही होती है किंतु उनके होमवर्क पूरा करने एवं उनकी प्रवृत्ति के सुधार के लिए थोड़ा-सा चमकाना आवश्यक होता है, तथा मोबाइल देखने अथवा परिवार के बिगड़े हुए माहौल एवं मोहल्ले में खेलते वक्त मित्रों से सीखी हुई गलत आदतों से यदि स्कूल और कक्षा का वातावरण खराब हो रहा हो तो उस समय इस प्रकार के बच्चों को समझाइश के साथ-साथ फटकार एवं शारीरिक दंड के नाते, कान पकड़कर बेंच पर खड़ा करना या कक्षा से बाहर निकालना अथवा कभी-कभी एक हल्की सी चपत लगा देना यह आवश्यक होता है। क्योंकि जब तक बच्चे के मन में भय उत्पन्न नहीं होगा तब तक वह अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर सकता।

शिक्षाविद् रमेशचन्द्र चन्द्रे ने कहा कि कक्षा छठी से लेकर कक्षा बारहवीं तक जिन्हें हम बच्चा समझते हैं वह वयस्कों के सारे गुण- अवगुण सीख जाता है जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से एवं उसके आपस के वार्तालाप से स्कूल में सबको पता हो जाता है।इसलिए कक्षा एवं स्कूल का वातावरण खराब ना हो तथा विद्यार्थी गलत दिशा में नहीं जाए इसलिए प्राथमिक तौर पर उन्हें समझाइश देने के साथ-साथ दंड की व्यवस्था अनिवार्य होती है चाहे फिर वह कानूनी हो या थोड़ा शारीरिक।

किंतु माता पिता सहित सभी लोगों का यह मत रहता है कि बच्चे को बिल्कुल भी दंड नहीं दिया जाए। इस मानसिकता के कारण बच्चे भी छोटे-मोटे दंड को जिस तरीके से घर में अभिव्यक्त करते हैं तथा सुनकर उसके अभिभावक खतरनाक कल्पना लोक में चले जाते है तथा उस दंड को बड़ा भारी समझकर कभी-कभी सोशल मीडिया का सहारा लेते है और अखबार वालों के पास चले जाते है, ऐसा करके वह प्रसिद्धि तो प्राप्त कर लेते है किंतु अनजाने में वह अपने बच्चों का ही नुकसान करते है।

शिक्षाविद् रमेशचन्द्र चन्द्रे ने कहा कि यह सब देखकर जब स्कूल के शिक्षक-शिक्षिकाओं को यह लगने लगता है कि जिस बच्चे के माता- पिता जरूरत से ज्यादा संवेदनशील है तथा बात बात पर शिकवा-शिकायत करते हैं तो वह उस पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, फिर वह छात्र कुछ भी करें पर शिक्षक उसकी प्रशंसा के पुल बांधते हैं और उसकी सकारात्मक गतिविधियों को ही अभिभावक के सामने रखते हैं,अभिभावक खुश हो जाता है किंतु इस कारण उस बच्चे की सारी विकास यात्रा गलत दिशा में चली जाती है।

शिक्षाविद् रमेशचन्द्र चन्द्रे ने कहा कि इसलिए स्कूल में यदि आप अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, संस्कार, व्यवहार इत्यादि सीखने के लिए भेजते हैं तो थोड़ा धैर्य रखिए और मीडिया वालों से भी निवेदन है कि वह स्कूलों के काम में सीधे-सीधे हस्तक्षेप ना करें क्योंकि आजकल अवैध यूट्यूब चैनल चलाने वाले हजार बारह सौ का एक माइक लेकर स्कूलों में पहुंच जाते हैं और स्कूल स्टॉफ और प्राचार्य को धमकाते हैं, कभी-कभी वे लोग गैर कानूनी वसूली भी करते पाए जाते हैं किंतु इस प्रकार की कार्यवाही से शिक्षा क्षेत्र का भट्टा बैठ जाएगा और शिक्षक मन लगाकर काम नहीं करेगा क्योंकि शिक्षक ही ऐसा एक तत्व है जिस को सम्मान देकर ही उस से काम लिया जा सकता है अन्यथा-भविष्य में परिणाम क्या निकलेंगे? यह तो ईश्वर ही बता सकता है?

90 प्रतिशत से कम ई-अटेंडेंस वाले अतिथि शिक्षकों से 10 जुलाई तक मांगे गए अभ्यावेदन

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में कार्यरत ऐसे अतिथि शिक्षक,जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विशेष परिस्थितियों के कारण 90 प्रतिशत ई-अटेंडेंस सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं अथवा जिनकी उपस्थिति 90 प्रतिशत से कम रही है तथा इस सत्र में री-ज्वाइनिंग नहीं हो सकी है,उनसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा अभ्यावेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया, कि संबंधित अतिथि शिक्षक अपने आवेदन दस्तावेजी साक्ष्यों सहित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के ई-मेल deonee-mp@nic.in पर 10 जुलाई 2026 तक भेज सकते हैं। हार्डकॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी, केवल ई-मेल से प्राप्त आवेदन ही मान्य होंगे। आवेदन के साथ महिला अतिथि शिक्षकों के मातृत्व अवकाश अथवा चाइल्ड केयर संबंधी कारण,प्रतियोगी या शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होने, नेटवर्क अथवा तकनीकी समस्या, गंभीर बीमारी,विवाह अथवा परिवार में आकस्मिक मृत्यु जैसे कारणों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना होंगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य विशेष कारण हो, तो उसका भी उल्लेख प्रमाण सहित किया जा सकता हैं।

घरेलू गैस सिलेंडरों की डिलीवरी 15 दिन बाद भी नहीं हो रही, कालाबाजारी और व्यावसायिक उपयोग के आरोप, उठे सवाल

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पिपलिया क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति व्यवस्था इन दिनों उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। गैस सिलेंडर बुक कराने के बाद भी उपभोक्ताओं को 15-15 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। समय पर सिलेंडर नहीं मिलने से परिवारों के सामने रसोई का संकट खड़ा हो गया है और लोगों में गैस एजेंसी की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। स्थानीय नागरिक मुरली जजवानी ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर बुक कराने के बावजूद निर्धारित समय पर उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। कई उपभोक्ताओं को लगातार एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि आम उपभोक्ताओं को जहां लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, वहीं कालाबाजारी करने वालों को तत्काल गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र के कई होटलों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है। ऐसे प्रतिष्ठानों को नियमित रूप से सिलेंडर उपलब्ध हो रहे हैं, जबकि घरेलू उपभोक्ता गैस के लिए परेशान हैं। यह घरेलू गैस सिलेंडरों के नियमों का उल्लंघन है और इसकी जांच की जानी चाहिए। मुरली जजवानी का कहना है कि प्रतिदिन बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर कालाबाजारी के लिए पहुंचते है, लेकिन आम उपभोक्ताओं तक समय पर सिलेंडर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे लोगों के मन में वितरण व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने संबंधित गैस कंपनी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि कहीं कालाबाजारी या घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग हो रहा है तो संबंधित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि घरेलू उपभोक्ताओं को बुकिंग के बाद निर्धारित समय सीमा में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

अधिकारियों को बताए साइबर क्राइम से बचने के उपाय

जबलपुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्ट्रेट कार्यालय स्थित सभा भवन में आज सोमवार को मध्य प्रदेश साइबर पुलिस द्वारा साइबर सिक्योर 2026 के तहत विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, नगर निगम आयुक्त रामप्रकाश अहिरवार, अपर कलेक्टर नीता राठौर, रविशंकर राय, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक गहलोत की मौजूदगी में संपन्न हुए इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को साइबर खतरों के प्रति जागरूक किया गया।

मॉनिटर लिजार्ड (गोह) के अवशेष (हत्था जोड़ी) की अवैध बिक्री करते हुए तीन आरोपी गिरफ्तार

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। वनमण्डलाधिकारी, मंदसौर को प्राप्त गोपनीय सूचना के आधार पर नेहरू बस स्टैंड स्थित नेहरू पार्क गेट के समीप कुछ व्यक्तियों द्वारा वन्यजीव के अवशेषों का अवैध विक्रय किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही वनमण्डलाधिकारी द्वारा तत्काल एक विशेष दल गठित कर मौके पर कार्रवाई हेतु रवाना किया गया। मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर दल ने 01 महिला एवं 02 पुरुषों को मॉनिटर लिजार्ड (गोह) के अंग (हत्था जोड़ी) कुल 19 नग के साथ अवैध बिक्री करते हुए गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुरेश सिंह पिता मलेसिंह पारदी, उम्र 54 वर्ष, करोल सिंह पिता मुछालसिंह पारदी, उम्र 36 वर्ष, भारतबाई पति सुरेश पारदी, उम्र 52 वर्ष है। तीनों आरोपी ग्राम रूपावली, पोस्ट साबाखेड़ा, जिला मंदसौर के निवासी हैं। मॉनिटर लिजार्ड (गोह) वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संरक्षित वन्यजीव है जिसके तहत आरोपियों के विरुद्ध परिक्षेत्र मंदसौर अंतर्गत वन अपराध प्रकरण क्रमांक 3832/16 विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां माननीय न्यायिक दंडाधिकारी महोदय द्वारा उन्हें दिनांक 15 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। प्रकरण में विस्तृत विवेचना जारी है। उक्त कार्रवाई में पुष्कर मालवीय, प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी मंदसौर, सोनू नागदा, स्टेनो, नरेंद्र मालवीय, वनरक्षक, मयूरराज सिंह चौहान, वनरक्षक, किरणसिंह राठौर, वनरक्षक, राधुदामा, वनरक्षक, भरत यादव, वनरक्षक, आशीष मालवीय तथा राजेशसिंह राजपूत का सराहनीय योगदान रहा।

मंदसौर में विकास के नाम पर विनाश का खेल, अमृत 2.0 और ड्रेनेज प्रोजेक्ट बना जनता के लिए जानलेवा मुसीबत-राजेश रघुवंशी

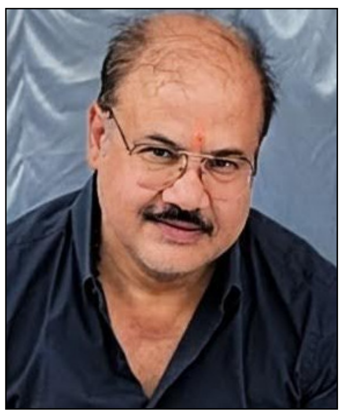

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मंदसौर शहर में अमृत 2.0 और ड्रेनेज प्रोजेक्ट के नाम पर मची महा-लापरवाही को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश रघुवंशी (प्रभारी विदिशा) ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मंदसौर शहर में सीवरेज और ड्रेनेज व्यवस्था को सुधारने के नाम पर जनता के पैसों की खुली बर्बादी और उनकी जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।

रघुवंशी ने आधिकारिक टेंडर शर्तों का हवाला देते हुए बताया कि लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपये के इस भारी-भरकम अमृत 2.0 सीवरेज प्रोजेक्ट के नियमों की जमीन पर खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। टेंडर के स्पष्ट नियमों और तकनीकी मापदंड के अनुसार ठेकेदार को पूरा शहर या पूरी सड़कें एक साथ खोदकर नहीं पटकनी हैं, बल्कि काम को चरणबद्ध तरीके से टुकड़ों में करना है। नियम के अनुसार ठेकेदार एक बार में केवल 100 से 200 मीटर का पैच ही खोद सकता है और उस हिस्से में पाइपलाइन डालने व उसका हाइड्रोलिक टेस्ट करने के तुरंत बाद, अधिकतम 24 से 48 घंटे के भीतर गड्ढे को मिट्टी-मुरम से भरकर समतल करना अनिवार्य है ताकि यातायात बाधित न हो। इसके बाद अधिकतम 15 से 30 दिनों के भीतर सड़क को उसके मूल स्वरूप में डामरीकरण या कंक्रीट से मरम्मत करना ठेकेदार की कानूनी जिम्मेदारी है, जिसके लिए टेंडर में अलग से करोड़ों का बजट सुरक्षित रखा गया है।

रघुवंशी ने ठेकेदार और प्रशासनिक अधिकारियों की जुगलबंदी पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निर्धारित सड़कों पर काम करने का ढंग पूरी तरह गैर-जिम्मेदाराना है। ठेकेदार ने टेंडर के नियमों को ताक पर रखकर पूरी सड़कों को एक साथ खोदकर छोड़ दिया है और वहां से उखड़ी मिट्टी को सड़कों पर ही फैला दिया है। सबसे गंभीर और घोर लापरवाही यह है कि इस संवेदनशील काम को बारिश के मौसम में भी बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के जारी रखा गया है। मानसून और बारिश के समय इस तरह की खुदाई करना प्रशासनिक अदूरदर्शिता और जनता के प्रति आपराधिक लापरवाही को दर्शाता है, क्योंकि बारिश के पानी से मिलकर यह खुली मिट्टी अब एक जानलेवा और गहरे दलदल में तब्दील हो चुकी है। इस फिसलन भरे रास्ते पर रोजाना दोपहिया वाहन चालक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, चार पहिया गाड़ियां और एंबुलेंस तक धंस रही हैं, तथा स्कूली बच्चों व बुजुर्गों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है। निर्माण स्थलों पर न तो कोई सुरक्षा बैरिकेड्स लगाए गए हैं और न ही रात के समय चमकने वाले रेडियम संकेतक, जो सीधे तौर पर टेंडर की शर्तों और सार्वजनिक सुरक्षा नियमों का खुला उल्लंघन है।

रघुवंशी ने जिला प्रशासन और नगर पालिका से मांग की है कि इस महा-लापरवाही को तुरंत ठीक किया जाए और सभी प्रभावित क्षेत्रों में अगले 48 घंटों के भीतर युद्धस्तर पर काम कर सड़कों से दलदली मिट्टी हटाई जाए और वहां मुरम-गिट्टी डालकर सड़कों को तुरंत चलने योग्य बनाया जाए। टेंडर की शर्तों का उल्लंघन करने वाले लापरवाह ठेकेदार पर तत्काल भारी जुर्माना (पेनाल्टी) लगाया जाए और उसके भुगतान पर रोक लगाकर काम की उच्च स्तरीय तकनीकी जांच कराई जाए। यदि प्रशासन ने इस नरक जैसी स्थिति से जनता को तुरंत मुक्ति नहीं दिलाई, तो कांग्रेस पार्टी आम जनता को साथ लेकर नगर पालिका का अनिश्चितकालीन घेराव करेगी और जन-आंदोलन छेड़ेगी। रघुवंशी नें कहा है कि इस पूरी जानलेवा लापरवाही, महाभ्रष्टाचार और टेंडर घोटाले की परतों को खोलने के लिए कांग्रेस पार्टी सूचना के अधिकार का सहारा लेगी ताकि अधिकारियों और ठेकेदार की सांठगांठ को कानूनी रूप से बेनकाब किया जा सके।

एक पेड मां के नाम अभियान अन्तर्गत पौधारोपण करें- कलेक्टर समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न

रतलाम/ प्रवीण व्यास/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में कलेक्टर श्रीमती मिशा सिंह की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सीएम हेल्पलाईन, समयावधि पत्रों एवं अन्य विषयों पर विभाग वार समीक्षा कर विभाग प्रमुखों को आवश्यक निर्देश दिए गये । बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री वैशाली जैन, एडीएम श्री ब्रजेंद्र कुमार रावत, आयुक्त नगर निगम श्री अनिल भाना सहित विभिन्न एसडीएम तथा विभाग प्रमुख उपस्थित थे।

बैठक में एक पेड मां के नाम अभियान, मानसून पूर्व विभागीय तैयारियां 2047 विजन डाक्यूमेंट, समय अवधि पत्रों की समीक्षा, सीएम मॉनिट प्रकरणों के संबंध में विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देशित किया सभी विभाग प्रमुख एक पेड मां के नाम अभियान अर्न्तगत स्वयं लक्ष्य निर्धारण करें। अधिक से अधिक पौधारोपण कर इसकी अंकुर वायुदूत एप पर लोकेशन आधारित फोटोग्राफी प्रविष्टि आनलाईन अंकित की जाए। बारिश के दौरान पंचायत स्तर तक अधिकारी कर्मचारियों के ड्युटी आर्डर की सूची साझा की जाए। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में हामगार्ड जवानों की ड्यूटी लगाई जाए। झरनें एवं प्रमुख स्थानों पर साइनेज लगाए जाए। जर्जर भवनों की विभागवार सूची अनुसार अनुपयोगी घोषित करवा कर डिस्मेंटल किया जाए। पेड़ो की छटाई करें।

बैठक में कलेक्टर ने मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को तारों को व्यवस्थित करने, ट्रांसफार्मर को व्यवस्थित करनें, तार एवं पोल की ऊंचाई निर्धारित मानक अनुसार सुनिश्चित करने, बिजली चोरी रोकने, अमानक कनेक्शन हटाने आदि के संबंध में विधिसंगत कार्यवाही करने के निर्देश दिए । निगम आयुक्त को सड़क पर गड्ढे भरवाने तथा पानी की उचित प्रकार निकासी के लिए निर्देशित किया गया ताकि दुर्घटना ना हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत मलवासा का पाइंट रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त भ्रमण कर प्रतिवेदन देने हेतु कहा गया। समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान शासकीय योजनाओं में बैंक आधारित भुगतान के लिए अधिकारियों को शुक्रवार के दिन हितग्राहियों को ले जाकर लाभ दिलानें हेतु निर्देशित किया गया। कलेक्टर ने सभी विभागीय अधिकारियों को रूफ वाटर हार्वेस्टिंग इंस्टाल करवानें के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम जावरा को जावरा चौपाटी से रास्ते की जमीन पर रजिस्ट्री संबंधी मामले में मौके पर परीक्षण करने तथा मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार खेल मैदान बनवाने के लिए स्थान चिन्हांकन कर आगामी कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

ध्वजा दर्शन प्रभु दर्शन के समान, दूर से ध्वजा देखकर भी करें नमो जिनाणं का स्मरण - मुनि विरलविनय विजय

मंदसौर/ भारतसिंह तोमर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। पिपलिया नगर के श्री विमलनाथ जैन मंदिर में रविवार को 54 वें ध्वजारोहण महोत्सव का आयोजन अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। महोत्सव में बड़ी संख्या में जैन समाज के महिला-पुरुष, युवा एवं बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर धर्मलाभ प्राप्त किया। व्याख्यान को संबोधित करते हुए मुनि विरलविनय विजय महाराज ने कहा कि जैन मंदिर की ध्वजा केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि श्रद्धा, आस्था और आत्मकल्याण का संदेश देने वाली प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति बस, ट्रेन या किसी अन्य वाहन से यात्रा कर रहा हो और दूर से किसी जैन मंदिर की ध्वजा दिखाई दे, तो श्रद्धापूर्वक णमो जिनाणं का स्मरण करते हुए ध्वजा के दर्शन करना चाहिए। ऐसे भावपूर्वक किए गए ध्वजा दर्शन से भी प्रभु दर्शन के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मुनिश्री ने कहा कि मंदिर पर ध्वजा चढ़ाने का सौभाग्य अत्यंत दुर्लभ होता है। ध्वजारोहण का लाभ लेने वाले परिवार को अपार पुण्य की प्राप्ति होती है तथा अनेक तीर्थों की यात्रा के समान धर्मलाभ मिलता है। उन्होंने बताया कि जैन धर्म की पंचरंगी ध्वजा के पाँच रंग पंच परमेष्ठी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुकृका प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही ये पाँच महाव्रतों एवं जैन धर्म के उच्च आदर्शों के प्रतीक भी हैं, जो प्रत्येक श्रद्धालु को सत्य, अहिंसा, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश देते हैं। महोत्सव की शुरुआत प्रातः 4 बजे मंदिर परिसर में सत्तरभेदी पूजा से हुई। इसके पश्चात मुनिश्री के निश्रा में सकल जैन संघ की उपस्थिति में लाभार्थी कुमठ परिवार ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजा फहराते ही मंदिर परिसर जय जिनेन्द्र और मंगलध्वनि से गूंज उठा। इसके बाद सामूहिक चेत्यवंदन, आरती एवं शांति कलश का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर धर्म आराधना की। जैन संघ के अध्यक्ष वीरेन्द्र राणावत ने आभार माना।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर चलकर ही सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण संभव : मदनलाल धाकड़

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। अठाना में भारतीय जनसंघ के संस्थापक, प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक, शिक्षाविद् एवं महान देशभक्त डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती स्थानीय नगर परिषद परिसर स्थित श्री पंचमुखी बालाजी मंदिर में श्रद्धा, सम्मान एवं उत्साह के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने डॉ. मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा उनके राष्ट्रवादी विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता मदनलाल धाकड़ ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी केवल एक राजनेता ही नहीं, बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वाभिमान के सच्चे प्रहरी थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में देशहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत की एकता के लिए संघर्ष करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी का सपना एक सशक्त, समृद्ध और अखंड भारत का था, जिसे आज देश नई दिशा में साकार होते देख रहा है। उनके विचार आज भी प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणास्त्रोत हैं।

मदनलाल धाकड़ ने कहा कि युवा पीढ़ी को डॉ. मुखर्जी के जीवन से प्रेरणा लेकर राष्ट्रसेवा, सामाजिक समरसता और जनकल्याण के कार्यों में आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम की भावना ही डॉ. मुखर्जी के जीवन का मूल मंत्र था और यही भावना भारत को विश्व पटल पर और अधिक गौरवशाली बनाएगी।

इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सत्यनारायण सेन, वरिष्ठ पार्षद एवं एल्डरमैन लोकेंद्र सिंह लकी बना, अशोक कारपेंटर, रामलाल प्रजापत, संजय नरवाडिया, गोपाल नरवाडिया, सामाजिक कार्यकर्ता अमर सिंह राजपूत सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन, व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। शांतिलाल चौहान द्वारा फोटो प्रेषित है।

रेडक्रॉस के निःशुल्क नेत्र शिविर में 200 नागरिकों का हुआ नेत्र परीक्षण

37 मोतियाबिंद मरीजों की हुई पहचान, चश्मे एवं आई ड्रॉप्स का किया गया वितरण

नीमच/ सतीश सैन/ दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में आमजन को बेहतर नेत्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी, नीमच एवं गोमाबाई नेत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को रेडक्रॉस भवन में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। कलेक्टर एवं जिला रेडक्रॉस सोसायटी के अध्यक्ष श्री हिमांशु चंद्रा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में बड़ी संख्या में नागरिकों ने लाभ प्राप्त किया।

शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा 200 नागरिकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कर आवश्यक परामर्श दिया गया। साथ ही जरूरतमंद हितग्राहियों को निःशुल्क चश्मे एवं आई ड्रॉप्स वितरित किए गए। परीक्षण के दौरान 37 मोतियाबिंद मरीजों की पहचान की गई, जिन्हें आगे की जांच एवं उपचार के लिए रेफर किया गया। इस पहल से अनेक नागरिकों को समय रहते नेत्र रोगों की पहचान एवं उपचार की सुविधा प्राप्त हुई।

शिविर में चिकित्सकों ने उपस्थित नागरिकों को नेत्रों की नियमित जांच कराने, आंखों की स्वच्छता बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की दृष्टि संबंधी समस्या होने पर तत्काल विशेषज्ञ से परामर्श लेने की सलाह दी। शिविर में रेडक्रॉस एवं गोमाबाई नेत्रालय की टीम ने सेवाभाव के साथ व्यवस्थाएं संभाली, जिससे लाभार्थियों को सुगमता से स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकीं।

शिविर के सफल आयोजन में जिला पंचायत सीईओ एवं प्रशासक श्री अमन वैष्णव, डिप्टी कलेक्टर एवं सहायक प्रशासक सुश्री श्रुति भायड़िया के निर्देशन में रेडक्रॉस सचिव डॉ. स्वप्निल वधवा, गोमाबाई नेत्रालय के चिकित्सकों एवं रेडक्रॉस के कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कलेक्टर श्री सिंह की अध्यक्षता में एनकॉर्ड समिति की बैठक सम्पन्न

जबलपुर /दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय में जिला स्तरीय एनकॉर्ड नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर नीता राठौर एवं रविशंकर राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री सिंह ने 15 जुलाई से 31 जुलाई तक शैक्षणिक संस्थानों में चलने वाले नशा मुक्ति अभियान की समय रहते सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने अभियान को व्यापक स्वरूप देने के लिए शहर के प्रमुख मॉल, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर नुक्कड़ नाटकों, का आयोजन करने तथा इस अभियान से आमजनों को जोड़ने मैराथन जैसी गतिविधियों के माध्यम से नशा मुक्ति का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

कलेक्टर श्री सिंह ने स्कूलों के 100 मीटर के दायरे के भीतर पान, गुटखा के ठेले-टपरों को हटाने अभी तक की गई कार्यवाही की जानकारी भी ली। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों के कारोबारियों के खिलाफ पुलिस की कार्यवाही लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि रेल मार्ग से आने वाले मादक पदार्थों पर भी जीआरपी एवं आरपीएफ द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है।

सम्पादकीय

भारत में क्विक कॉमर्स का बढ़ता असर, किराना स्टोर कैसे करेंगे मुकाबला?

किराना दुकानें एक ऐसी प्रजाति हैं जो सन 1991 के बाद उभरे नए खुदरा कारोबारी स्वरूपों से मिल रही तमाम चुनौतियों के बीच भी फलती-फूलती रही हैं। लेकिन अब क्विक कॉमर्स के उभार के साथ उनको असली चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। फ्लिपकार्ट मिनट्स जो इस क्षेत्र में सबसे नया प्रवेशकर्ता है उसका कहना है कि वह इसे छोटे शहरों तक ले जाएगा और अन्य शायद उसका अनुसरण करेंगे।

क्विक कॉमर्स पुरानी किराना दुकानों का ही कहीं अधिक ताकतवर स्वरूप है। अपने अच्छे दिनों में किराना दुकानें ही भारत में क्विक कॉमर्स की रीढ़ की तरह थीं। वे हमारे पास-पड़ोस में और घर के आसपास ही मौजूद रहतीं और केवल एक फोन कॉल पर ऑर्डर हमारे घर पहुंचा दिया करती थीं। आप किसी को दुकान भेजकर 10 मिनट से भी कम समय में सामान मंगवा सकते थे। ये किराना दुकानदार ग्राहकों से एक खास किस्म के रिश्ते में बंधे रहते थे।

उन दिनों मेरा नियमित किराना दुकान मालिक मुझे फोन करके पूछता था कि क्या मैं कहीं और से खरीद रहा हूं, क्योंकि उसने देखा कि मेरी खरीदारी में पांच महंगे खाद्य पदार्थ गायब थे (दरअसल मेरा एक बच्चा कॉलेज के लिए घर छोड़ चुका था)। उसने मुझे उधार की सुविधा दी, मेरी दुर्लभ लेकिन पसंदीदा चाय ब्रांड के दो पैक सुरक्षित रखे। अगर मैं सतर्क नहीं रहती तो वह हर मौके पर मुझसे अतिरिक्त कमाई करने की कोशिश करता था, फिर भी हमारे बीच गहरा रिश्ता था।

पिछले 20 वर्षों में अचल संपत्ति कीमतों में तेजी आई और इसके चलते किराना दुकानें उच्च आय वाले प्रमुख इलाकों से बाहर हो गईं। इससे उनकी आपूर्ति सेवा प्रभावित हुई। जैसे-जैसे नए ब्रांड बढ़े कार्यशील पूंजी की जरूरत भी बढ़ी। बड़े किराना स्टोर आधुनिक होने लगे, बड़ी कंपनियों द्वारा उन्हें अपने डिजिटल वितरण नेटवर्क में खींचा गया और उन्हें डेटा व ग्राहक प्रबंधन उपकरण दिए गए। हालांकि उनकी ग्राहक सेवा कमजोर पड़ने लगी। उनका कारोबारी मॉडल इस पर आधारित था कि मालिक दुकान में बैठा रहे लेकिन अगली पीढ़ी ऐसा करने को तैयार नहीं है।

क्विक कॉमर्स इसका फायदा उठाने के लिए सामने आया। उन्होंने एक जाने पहचाने काम को करने का एक नया और बेहतर तरीका पेश किया। क्विक कॉमर्स ताजा फल-सब्जी, कुछ टिकाऊ सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी चीजें उपलब्ध कराता है। ये ऐसे उत्पाद हैं जिन्हें किराना दुकान नहीं संभाल सकतीं। इसके अलावा वे बहुत तेजी से सामान पहुंचाकर एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करते हैं। पश्चिम के सुपर मार्केट जैसे आधुनिक व्यापार के उलट क्विक कॉमर्स ग्राहकों से यह अपेक्षा नहीं करता कि वे स्टोर पर जाएं, लेबल लगे गलियारों के बीच से रास्ता निकालें और बिल भुगतान के लिए कतार लगाकर खड़े हों।

लेकिन ग्राहक ने इस आधुनिकता का मूल्य किराना से भी बदतर माना। आधुनिक व्यापार का आर्थिक मॉडल (बड़े पैमाने पर काम करों, सस्ता खरीदो और सस्ता बेचो) भारत में अच्छी तरह काम नहीं कर पाया क्योंकि मांग की विविधता और अचल संपत्ति की लागत बहुत अधिक थी। भारत के लिए विशेष रूप से बनाई गई अवधारणाओं जैसे बिग बाजार आदि ने थोड़ी पकड़ बनाई लेकिन वे पैमाने को सहारा देने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

क्विक कॉमर्स की ताकत उसका काफी सक्षम और पूरी तरह डिजिटल अंतिम छोर समर्थन है। सैद्धांतिक रूप से यह पैमाने और समझदारी भरे उत्पाद मिश्रण प्रबंधन के साथ आय अर्जित करेगा। हमने बार-बार देखा है कि भारतीय बाजार अन्य बाजारों की तरह विकसित नहीं होते।

भारत के उपभोक्ता बाजार का सबसे बड़ा आकर्षण वे उत्पाद हैं जो बेहतर कार्यक्षमता प्रदान करते हैं। अन्य देशों में जो पैकेट बंद खाद्य क्रांति आई थी वह यहां नहीं आई। एमेजॉन इंटरनेट पर एक बड़े पारंपरिक बाजार का कहीं अधिक बेहतर स्वरूप देता है। क्विक कॉमर्स इस बात को स्वीकार करता है कि हम कितने असंगठित हैं।

भारत की विशालता और क्विक कॉमर्स कंपनियों की रणनीतिक पसंद के कारण किराना दुकानें बनी रहेंगी। हालांकि, कई दुकानें बंद हो जाएंगी और अन्य व्यवसायों की ओर मुड़ेंगी खासकर जब संपन्न उपभोक्ता दूर चले जाएंगे। आज जो नए, रोमांचक और छोटी चुनौती देने वाले ब्रांड्स उभर रहे हैं वे किराना दुकानों के जरिये व्यापक वितरण का कठिन रास्ता नहीं अपना रहे। इसके बजाय वे क्विक कॉमर्स द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे अपेक्षाकृत संपन्न और बढ़ते उपभोक्ता वर्ग पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

हमारा विशाल उपभोक्ता भारत अब और भी अधिक विशाल और ताकतवर हो गया है मानो उसे और ऊर्जा मिल गई हो। 1990 के दशक के उदारीकरण के पहले चरण में कीमतें घटीं और गुणवत्ता बढ़ी क्योंकि कर कम हुए और प्रतिस्पर्धा बढ़ी। उसके बाद आए चीनी उत्पादों ने बेहतर कीमत-प्रदर्शन अनुपात और रोजमर्रा के कई नए उत्पाद दिए जो पहले देखने को नहीं मिले थे। फिर आया एमेजॉन जो अपने विशाल उत्पाद-संग्रह, कीमतों और किसी भी नापसंद चीज को लौटाने की सुविधा के कारण अलग दिखा। और अब आया है क्विक कॉमर्स।

भले ही अंततः क्विक कॉमर्स पर कुछ हद तक लगाम लग जाए लेकिन ऐसा होगा तो इसलिए कि आपूर्तिकर्ताओं में विस्तार के लंबे दौर तक टिके रहने की क्षमता या धैर्य की कमी पड़ जाए या वे अपने कारोबार को अधिक लाभांश और बड़े टिकट आकार वाले उत्पादों की ओर मोड़ दें। उपभोक्ता भारत बहुत दिलचस्प तरीकों से छलांग लगाता है। वह विकास के उन कई चरणों को छोड़ देता है, जिनसे दूसरे बाजार गुजरे हैं। यदि आप उसे ऐसा मूल्य दें जिसे ग्राहक वास्तव में बेहतर माने और उससे यह अपेक्षा न करें कि वह अपनी आदतें या तौर-तरीके बदले तो आपकी सफलता तय है।

गुरुतत्त्व एवं सहजयोग ध्यान

पूज्य श्री माताजी की अमृतवाणी के अनुसार गुरु वह है जिसमें गुरुत्वाकर्षण हो–अर्थात ऐसा व्यक्तित्व जो अपने ज्ञान, चरित्र, स्थिरता और प्रेम से जिज्ञासुओं के चित्त को सहज ही आकर्षित कर सके। जैसे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से सबको धारण करती है, वैसे ही सच्चा गुरु अपनी गंभीरता, उत्तरदायित्व और आत्मिक शक्ति से समाज को दिशा देता है। श्री माताजी स्पष्ट करती हैं कि गुरु बनने के लिए केवल विद्वत्ता पर्याप्त नहीं, बल्कि चरित्र का वजन, गरिमा का वजन, आचरण का वजन, श्रद्धा का वजन और आत्मप्रकाश का वजन होना आवश्यक है। तुच्छता, मिथ्याभिमान, क्रोध, कटु वाणी और अभद्र व्यवहार गुरुतत्त्व के विरोधी हैं। सहजयोग ध्यान इसी गुरुतत्त्व को भीतर जागृत करने का सरल और प्रभावी माध्यम है। नियमित ध्यान से साधक की कुंडलिनी जागृत होकर उसके मन, बुद्धि और चित्त को संतुलित करती है, जिससे विनम्रता, प्रेम, क्षमा, करुणा और आत्मसंयम जैसे दिव्य गुण विकसित होते हैं। जब साधक सहजयोग के माध्यम से आत्मसाक्षात्कार प्राप्त करता है, तब उसके व्यक्तित्व में ऐसी आध्यात्मिक गरिमा और मधुरता प्रकट होती है कि उसका जीवन स्वयं दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाता है। यही वास्तविक गुरुतत्त्व है–जो उपदेश से अधिक अपने आचरण, स्थिरता और प्रेमपूर्ण वाणी से लोगों के हृदय को स्पर्श करता है। अतः श्री माताजी की अमृतवाणी हमें यह संदेश देती है कि सहजयोग ध्यान का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत शांति प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर ऐसा आध्यात्मिक गुरुत्व विकसित करना है, जिससे हमारा जीवन सत्य, प्रेम, करुणा, मर्यादा और विश्वकल्याण का माध्यम बन सके। यही गुरुतत्त्व की सच्ची साधना और सहजयोग का परम लक्ष्य है।

सीमा पर अविश्वास, बाज़ार में विश्वास – कितना उचित?

इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्र की दिशा केवल युद्धक्षेत्रों से नहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों से भी तय होती है। भारत सरकार द्वारा चार चीनी-लिंक्ड पावर उपकरण कंपनियों (जिनकी भारत में विनिर्माण इकाइयाँ हैं) को बिजली क्षेत्र की महत्वपूर्ण सरकारी परियोजनाओं में दो वर्ष के लिए बोली लगाने की अनुमति ऐसा ही एक निर्णय है। इसे महज़ व्यापारिक उदारीकरण मानना भूल होगी। यह उस द्वंद्व का प्रतीक है, जहाँ एक ओर आर्थिक विकास की आवश्यकता है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सुरक्षा का अटल दायित्व। गलवान की रक्तरंजित स्मृतियाँ आज भी राष्ट्रीय चेतना में अंकित हैं, पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्ण डी-एस्केलेशन अभी बाकी है और दोनों देशों के बीच विश्वास अब भी अधूरा है। फिर भी आर्थिक आवश्यकताओं ने संवाद के द्वार फिर खटखटाए हैं। प्रश्न केवल चीनी कंपनियों की वापसी का नहीं, बल्कि यह है कि क्या भारत इसे अपने रणनीतिक हितों के अनुरूप नियंत्रित कर पाएगा, या आर्थिक आवश्यकता धीरे-धीरे रणनीतिक निर्भरता में बदल जाएगी।

हर बड़े राष्ट्रीय निर्णय के पीछे आर्थिक यथार्थ की कठोर परत होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। भारत ऊर्जा संक्रमण, उच्च गति रेल, स्मार्ट सिटी, हरित अवसंरचना और नवीकरणीय ऊर्जा जैसी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं के निर्णायक दौर में है। इनके लिए भारी निवेश के साथ उन्नत तकनीक, तीव्र निष्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धी लागत आवश्यक है। वैश्विक स्तर पर कई चीनी कंपनियाँ कम समय और लागत में विशाल परियोजनाएँ पूरी करने में सक्षम हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी कंपनियाँ अपेक्षाकृत महँगी हैं, जबकि भारतीय उद्योग अभी सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं हैं। ऐसे में सस्ता और सक्षम विकल्प आकर्षित करता है। किंतु इतिहास चेतावनी देता है कि आज का आर्थिक लाभ, यदि दूरदृष्टि न हो, तो कल रणनीतिक स्वतंत्रता पर बोझ बन सकता है।

यहीं आर्थिक आवश्यकता और राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे कठिन टकराव सामने आता है। सुरक्षा एजेंसियों की आशंकाएँ पूर्वाग्रह नहीं, बल्कि वैश्विक अनुभवों पर आधारित हैं। अनेक चीनी कंपनियों और उनकी सरकार के निकट संबंधों को लेकर कई देश चिंता जता चुके हैं। यदि ऐसी कंपनियों की पहुँच बिजली ग्रिड, दूरसंचार नेटवर्क, रेलवे, बंदरगाह और डिजिटल अवसंरचना जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रों तक होती है, तो डेटा संग्रह, साइबर निगरानी, संभावित बैकडोर और लॉजिस्टिक नियंत्रण के जोखिम बढ़ जाते हैं। आज युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं, बल्कि डेटा, डिजिटल नेटवर्क और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं पर भी लड़े जाते हैं। ऐसे में प्रश्न यही है कि क्या औपचारिक सुरक्षा जाँच और कागजी मंजूरियाँ इन अदृश्य खतरों से देश की रक्षा कर पाएँगी, या यही ढील भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे महँगी कीमत बन जाएगी।

विडंबना यह है कि जब विश्व आर्थिक संतुलन की नई दिशा तय कर रहा है, तब भारत एक अलग द्वंद्व से गुजर रहा है। आज विश्व चीन प्लस वन रणनीति के तहत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन पर निर्भरता घटाकर भारत जैसे देशों की ओर आशा से देख रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है, किंतु इसी समय भारत चीनी कंपनियों के लिए नए आर्थिक द्वार खोल रहा है। यह हमारी दोहरी वास्तविकता को उजागर करता है। एक ओर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, तो दूसरी ओर वैश्विक उत्पादन व्यवस्था की जटिलता, जहाँ पूर्ण आर्थिक पृथक्करण व्यवहारिक नहीं। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि राष्ट्रीय हितों पर आधारित स्पष्ट शर्तों के बिना यह खुलापन तकनीकी निर्भरता, बाहरी नियंत्रण, आर्थिक दबाव और ऋण-जाल जैसी चुनौतियाँ बढ़ा सकता है। इसलिए निवेश का स्वागत तभी उचित है, जब वह भारत को सशक्त बनाए, निर्भर नहीं।

स्पष्ट है कि इस चुनौती का उत्तर न अतिवादी विरोध में है, न बिना शर्त स्वीकार्यता में। भारत को विवेकपूर्ण, नियंत्रित और राष्ट्रीय सुरक्षा-आधारित सहयोग की नीति अपनानी होगी। चीनी कंपनियों की भागीदारी केवल गैर-संवेदनशील क्षेत्रों तक सीमित रहे। प्रत्येक परियोजना में डेटा लोकलाइजेशन, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, स्थानीय सामग्री और भारतीय साझेदारी सुनिश्चित हो तथा हर चरण में कठोर साइबर सुरक्षा ऑडिट कराया जाए। साथ ही घरेलू उद्योगों को अनुसंधान, नवाचार, वित्तीय सहयोग और तकनीकी प्रोत्साहन मिले, ताकि दीर्घकाल में भारत बाहरी तकनीकी निर्भरता से मुक्त हो सके। यदि सस्ती परियोजनाओं के आकर्षण में इन सुरक्षा उपायों की अनदेखी हुई, तो आज का आर्थिक लाभ कल की रणनीतिक कमजोरी बन सकता है।

इस निर्णय की कूटनीतिक गूँज भी इसके आर्थिक प्रभावों जितनी दूरगामी है। लद्दाख में सैन्य और राजनयिक वार्ताएँ जारी हैं, किंतु विश्वास की पुनर्स्थापना अब भी अधूरी है। ऐसे समय में चीनी कंपनियों की वापसी का संदेश केवल बीजिंग ही नहीं, बल्कि पूरा विश्व देख रहा है। इसे एक ओर संतुलित और नियंत्रित सहयोग की नीति माना जा सकता है, तो दूसरी ओर यह आशंका भी है कि भारत अनजाने में अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी को आर्थिक अवसर दे रहा है। परिपक्व कूटनीति का अर्थ स्थायी शत्रुता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संतुलित संवाद है। किंतु यह तभी सार्थक होगा, जब उसकी नींव समानता, पारदर्शिता और पारस्परिक उत्तरदायित्व पर टिकी हो। आर्थिक संबंध किसी भी स्थिति में ऐसी निर्भरता में न बदलें, जो भविष्य में भारत की निर्णय-स्वतंत्रता को प्रभावित करे।

वास्तविक कसौटी चीनी कंपनियों की वापसी नहीं, बल्कि भारत की रणनीतिक दूरदृष्टि और नीति-परिपक्वता है। न भावनात्मक चीन-विरोध आर्थिक उन्नति का आधार बन सकता है, न अल्पकालिक आर्थिक लाभ के लिए सुरक्षा संबंधी आशंकाओं की उपेक्षा की जा सकती है। भारत को ऐसा संतुलन स्थापित करना होगा, जहाँ विकास, आत्मनिर्भरता, वैश्विक निवेश और राष्ट्रीय सुरक्षा साथ-साथ आगे बढ़ें। विवेकपूर्ण संतुलन, दूरदर्शी नीति, अटूट सुरक्षा-सतर्कता और स्वदेशी क्षमता निर्माण ही सशक्त भारत की नींव हैं। यदि भारत यह संतुलन साध लेता है, तो यह सीमित छूट केवल आर्थिक आवश्यकता का प्रतीक नहीं, बल्कि उस परिपक्व राष्ट्र की पहचान बनेगी, जो वैश्विक अवसरों का स्वागत करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा भी करता है। अंततः इतिहास सम्मान उन्हीं राष्ट्रों को देता है, जो क्षणिक लाभ नहीं, बल्कि दूरदृष्टि से अपना भविष्य गढ़ते हैं।

-प्रो. आरके जैन

कांग्रेस से कैसे छूटा राष्ट्रवाद का मुद्दा?

राष्ट्रीय राजनीति में चल रहे मंथन के दो पहलू हैं और चिंता मत कीजिए मैं मंत्रिमंडल के संभावित विस्तार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यह काम राजधानी के कमोबेश बेरोजगार अंदरूनी जानकारी वाले ज्ञानी लोगों के लिए छोड़ता हूं। मेरी रुचि दो ऐसी बातों में है जो विरोधाभासी नजर आती हैं लेकिन हैं नहीं। पहली बात यह कि भाजपा ने एक ऐसा राजनीतिक चमत्कार किया है कि वह लोक सभा में बहुमत से दूर रहने के बावजूद भारत को लगभग एकदलीय देश बनाने में कामयाब दिख रही है।

दूसरा चूंकि इसके लिए बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दलों में विभाजन, उन्हें साथ लेने या नष्ट करने का सहारा लिया जा रहा है इसलिए कांग्रेस देश में इकलौता ऐसा विपक्ष है जो अक्षुण्ण है। ऐसे में भारतीय राजनीति द्विदलीय भी नजर आती है। यह एकदम सहज और सरल समीकरण होता अगर कांग्रेस एक मजबूत चुनौती नजर आती। ऐसी दो दलीय व्यवस्था भाजपा को रास आएगी क्योंकि उसे केवल मजबूत क्षेत्रीय दलों के सामने ही संघर्ष करना पड़ता है। उनमें से अधिकांश को उसने नष्ट कर दिया है और अब अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती है।

यहां तीन सवाल पैदा होते हैं। पहला, मोदी-शाह की भाजपा कांग्रेस को इतना सहज प्रतिद्वंद्वी क्यों मानती है? दूसरा, कांग्रेस में क्या कमी है कि वह विश्वसनीय चुनौती नहीं बन पा रही? और तीसरा, कांग्रेस खुद को कैसे खड़ा कर सकती है?

पहले सवाल का जवाब आसान है- भाजपा चार इंजनों के सहारे आगे बढ़ रही है- कट्टर हिंदुत्व, उससे भी कट्टर राष्ट्रवाद, सक्षम और निष्पक्ष जनकल्याण और जबरदस्त अधोसंरचना विकास जो सबको नजर आ रहा है। कांग्रेस के पास इसकी विश्वसनीय काट नहीं है। और दूसरे सवाल का जवाब इसी में निहित है। कांग्रेस के मुताबिक अगर भाजपा सब कुछ गलत कर रही है तो आखिर वह सत्ता में आकर क्या करेगी?

अर्थव्यवस्था, सामरिक मुद्दों और रक्षा मामलों पर कांग्रेस का रुख भाजपा से अलग कैसे होगा? वह चीन, अमेरिका और पश्चिम एशिया से कैसे निपटेगी? रक्षा पर वह कितना खर्च करेगी? बीजेपी के विकल्प के रूप में इसका नजरिया क्या है? यह कहना कि बीजेपी 'भ्रष्ट, विकृत पूंजीवादी है और राष्ट्रीय हित से समझौता कर रही है' राजनीतिक बयानबाजी के लिए तो ठीक है लेकिन आप अलग क्या करेंगे? यदि कांग्रेस खुद को एक विकल्प मानती है और चाहती है कि मतदाता भाजपा पर उसे तरजीह दें तो उसे बताना होगा कि वह भाजपा से अलग कैसे है? कांग्रेस को पहले इन सवालों का जवाब देना होगा। और फिर उन चार इंजनों का मुकाबला करना होगा जिनके बारे में हमने कहा था कि वे भाजपा के वाहन को चला रहे हैं। पहला, हिंदुत्व। कांग्रेस को यहां भाजपा से होड़ करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिए। यह भाजपा का ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस सेंध नहीं लगा सकती। भले ही उसका शीर्ष नेतृत्व कितने ही मंदिरों का भ्रमण क्यों न कर ले?

-धनंजय राजौरा

डिजिटल क्रांति के दौर में बढ़ते साइबर अपराध, बड़ी चुनौती

डिजिटल क्रांति ने भारत को अभूतपूर्व गति, सुविधा और पारदर्शिता प्रदान की है। आज मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) ने सामान्य नागरिक के जीवन को सरल और सक्रिय बनाया है। भारत विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से उभर रहा है और 'डिजिटल इंडिया' तथा 'विकसित भारत-2047' का सपना इसी तकनीकी परिवर्तन पर आधारित है। किंतु इस उजले परिदृश्य के समानांतर एक भयावह अंधेरा भी तेजी से फैल रहा है-साइबर अपराधों का बढ़ता साम्राज्य। डिजिटल अरेस्ट, ऑनलाइन वित्तीय ठगी, फिशिंग, पहचान की चोरी, निवेश घोटाले, व्यक्तिगत गोपनीयता पर सेंध, सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, बाल यौन शोषण सामग्री का प्रसार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग आज केवल तकनीकी समस्या नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक नैतिकता के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। विडंबना यह है कि जिस तकनीक का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को सुरक्षित, सुविधाजनक और ज्ञानसमृद्ध बनाना था, वही तकनीक अपराधियों के लिए सबसे प्रभावी हथियार बनती जा रही है। इंटरनेट की असीम संभावनाओं का लाभ जितनी तेजी से समाज ने उठाया है, उतनी ही तेजी से अपराधियों ने भी उसे अपने हित में ढाल लिया है। परिणामस्वरूप डिजिटल दुनिया में विश्वास का संकट गहराता जा रहा है।

डिजिटल व्यवस्था की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है। जब कोई नागरिक मोबाइल पर क्यूआर कोड स्कैन करता है, यूपीआई से भुगतान करता है या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निवेश करता है, तब वह केवल तकनीक पर नहीं, बल्कि पूरे डिजिटल तंत्र की विश्वसनीयता पर भरोसा करता है। यदि यही भरोसा लगातार साइबर ठगी, फर्जी कॉल, फिशिंग, नितांत व्यक्तिगत सूचनाओं के सार्वजनिक होने के भय, निवेश घोटालों और पहचान की चोरी जैसी घटनाओं से टूटने लगे, तो डिजिटल अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर पड़ जाएगी। जिस प्रकार नकली मुद्रा का प्रसार पूरी आर्थिक व्यवस्था को संकट में डाल देता है, उसी प्रकार डिजिटल धोखाधड़ी का बढ़ना कैशलेस अर्थव्यवस्था की अवधारणा को कमजोर कर सकता है। परंपरागत अपराधों और साइबर अपराधों में मूलभूत अंतर है। पहले अपराध किसी निश्चित क्षेत्र तक सीमित रहते थे, अपराधी की पहचान और गिरफ्तारी की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती थी। आज साइबर अपराधी हजारों किलोमीटर दूर बैठकर कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। उसके लिए जोखिम न्यूनतम और लाभ अधिकतम है। यही असंतुलन साइबर अपराध को अत्यंत खतरनाक बनाता है। अपराध का यह नया स्वरूप सीमाओं, भाषाओं और कानूनों की पारंपरिक सीमाओं को भी चुनौती दे रहा है।

चिंता केवल आर्थिक अपराधों तक सीमित नहीं है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया मंचों पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के प्रचार-प्रसार के आरोपों ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। यदि लोकप्रिय डिजिटल मंचों पर पैसे लेकर ऐसे विज्ञापन प्रसारित हो सकते हैं, तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक विफलता भी है। प्रश्न यह भी है कि क्या सोशल मीडिया कंपनियां केवल स्वयं को तकनीकी मंच कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती हैं? जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता और एल्गोरिद्म यह तय करते हैं कि कौन-सा विज्ञापन किस व्यक्ति तक पहुंचेगा, तब उन मंचों की जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी हो जाती है। आज अनेक डिजिटल प्लेटफॉर्म आपत्तिजनक सामग्री हटाने का दावा करते हैं, किंतु व्यवहार में उनकी प्राथमिकता कई बार राजस्व और व्यावसायिक हित प्रतीत होती है। यदि बाल यौन शोषण, अश्लीलता, साइबर ठगी या संगठित अपराध से जुड़े विज्ञापन और सामग्री लंबे समय तक सक्रिय रह सकते हैं, तो यह केवल अपराधियों की सफलता नहीं, बल्कि डिजिटल मंचों की जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाए बिना डिजिटल समाज स्वस्थ नहीं रह सकता।

साइबर अपराध का सबसे दुखद पक्ष पीड़ित की मानसिक पीड़ा है। जीवनभर की बचत कुछ मिनटों में गायब हो जाती है। इसके बाद पुलिस, बैंक और साइबर हेल्पलाइन के चक्कर लगते हैं, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं होने के कारण अधिकांश मामलों में धन वापस नहीं मिल पाता। इससे नागरिक के भीतर व्यवस्था के प्रति अविश्वास पैदा होता है। यदि अपराधी को दंड न मिले और पीड़ित को राहत न मिले, तो कानून का भय भी समाप्त होने लगता है। भारत सरकार ने साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, हेल्पलाइन, साइबर क्राइम समन्वय केंद्र तथा डिजिटल सुरक्षा संबंधी अनेक पहलें शुरू की गई हैं। न्यायपालिका ने भी ऑनलाइन धोखाधड़ी को आर्थिक सुरक्षा से जोड़कर गंभीर चिंता व्यक्त की है। फिर भी नीति और उसके प्रभावी क्रियान्वयन के बीच बड़ी दूरी दिखाई देती है। शिकायत दर्ज होने के बाद शुरुआती कुछ घंटे सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यदि इसी अवधि में बैंक खाते फ्रीज कर दिए जाएं और धन के प्रवाह को रोक दिया जाए तो बड़ी राशि बचाई जा सकती है। लेकिन अक्सर कार्रवाई में देरी अपराधियों के पक्ष में चली जाती है।

डिजिटल सुरक्षा अब केवल पुलिस का विषय नहीं रही। यह आर्थिक नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, शिक्षा, प्रशासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा बहुआयामी प्रश्न बन चुकी है। विकसित देशों ने साइबर सुरक्षा को राष्ट्रीय सुरक्षा के समान महत्व दिया है। विशेष एजेंसियां, अत्याधुनिक तकनीक, प्रशिक्षित विशेषज्ञ, रियल टाइम डेटा साझा करने की व्यवस्था और कठोर दंडात्मक कानून वहां की व्यवस्था का हिस्सा हैं। भारत को भी इसी दिशा में और अधिक सुदृढ़ कदम उठाने होंगे। स्थानीय पुलिस को डिजिटल फॉरेंसिक, ब्लॉकचेन विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित जांच और अंतरराष्ट्रीय साइबर कानूनों का प्रशिक्षण देना समय की आवश्यकता है। इसके साथ ही नागरिक जागरूकता भी उतनी ही आवश्यक है। तकनीक जितनी उन्नत होगी, अपराधी भी उतने ही नए तरीके खोजेंगे। इसलिए विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और सामाजिक संगठनों के माध्यम से डिजिटल साक्षरता को जनआंदोलन बनाया जाना चाहिए। लोगों को संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल, निवेश योजनाओं और सोशल मीडिया के छल-प्रपंचों से बचने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि सुरक्षा का पूरा दायित्व नागरिक पर डालकर सरकार, बैंक और डिजिटल कंपनियां अपनी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकतीं। सुरक्षित डिजिटल वातावरण उपलब्ध कराना संस्थागत दायित्व है।

भ्रष्टाचार, लापरवाही और कमजोर केवाईसी व्यवस्था भी साइबर अपराध को बढ़ावा देती है। यदि फर्जी पहचान के आधार पर बैंक खाते खुलते हैं, यदि भुगतान प्लेटफॉर्म समय पर संदिग्ध लेन-देन नहीं रोकते, यदि आंतरिक मिलीभगत से अपराधियों को सुविधा मिलती है, तो यह केवल तकनीकी दोष नहीं बल्कि संस्थागत अपराध है। इसलिए पारदर्शी ऑडिट, कठोर उत्तरदायित्व और सख्त दंड व्यवस्था अनिवार्य होनी चाहिए। साइबर अपराध अब किसी एक देश की समस्या नहीं रहा। इंटरनेट की दुनिया में अपराधी सीमाओं से मुक्त हैं, इसलिए समाधान भी वैश्विक होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र सहित विश्व की प्रमुख शक्तियों को साइबर अपराध के विरुद्ध साझा कानूनी ढांचा, त्वरित सूचना आदान-प्रदान और तकनीकी सहयोग विकसित करना होगा। जिस प्रकार आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक सहयोग आवश्यक माना गया, उसी प्रकार साइबर अपराध के विरुद्ध भी विश्वव्यापी समन्वय समय की मांग है।

अंततः डिजिटल क्रांति का वास्तविक उद्देश्य केवल तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि मानव जीवन को अधिक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक बनाना है। यदि यही क्रांति भय, असुरक्षा और अविश्वास का कारण बनने लगे, तो उसकी सफलता अधूरी रह जाएगी। डिजिटल भारत की वास्तविक शक्ति उसके ऐप्स, सर्वरों और आंकड़ों में नहीं, बल्कि उस विश्वास में निहित है, जिसके साथ करोड़ों नागरिक प्रतिदिन अपने मोबाइल पर एक-एक लेन-देन करते हैं। आज आवश्यकता केवल तकनीकी समाधान की नहीं, बल्कि तकनीक, नैतिकता, कानून और उत्तरदायित्व के समन्वित मॉडल की है। सरकार को कठोर कानून, त्वरित न्याय और सक्षम जांच तंत्र विकसित करना होगा, डिजिटल कंपनियों को अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन करना होगा, वित्तीय संस्थानों को सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ानी होगी और नागरिकों को डिजिटल अनुशासन अपनाना होगा। साइबर अपराध और भारतीय डिजिटल जीवनशैली के बीच संतुलन ही विकसित भारत की सबसे बड़ी कसौटी है। यदि यह संतुलन स्थापित हो गया, तो डिजिटल भारत विश्व का सबसे विश्वसनीय डिजिटल लोकतंत्र बन सकता है, अन्यथा तकनीकी उपलब्धियां भी अविश्वास के बोझ तले दम तोड़ देंगी।

-ललित गर्ग

पर्याप्त संसाधनों के बाद भी बाढ़ (अतिवृष्टि) और सूखे(अनावृष्टि)

भारत भौगोलिक तौर पर बड़ा विशाल का देश है। जहां एक ओर हमारे पास विश्वस्तरीय वैज्ञानिक संस्थान, मौसम पूर्वानुमान प्रणाली, उपग्रह तकनीक, विशाल प्रशासनिक तंत्र और आपदा प्रबंधन के लिए अलग मंत्रालय है, तो दूसरी ओर हर वर्ष भीषण गर्मी, सूखा, अतिवृष्टि और बाढ़ लाखों लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त कर देते हैं। जब संसाधनों की कमी नहीं है, तब तैयारी में कमी और इतनी जानमाल का नुकसान क्यों क्यों दिखाई देता है? यह समस्या किसी एक शहर, राज्य या क्षेत्र तक सीमित नहीं रही। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक हिस्से भीषण लू और सूखे से जूझते हैं, वहीं असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केरल तथा महानगरों में कुछ घंटों की बारिश भी बाढ़ का रूप ले लेती है। हाल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने सड़कें, पुल और गांवों को भारी नुकसान पहुँचाया। इसी समय देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप भी देखने को मिला।

यह केवल प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि हमारी विकास नीति, प्रशासनिक तैयारी और दीर्घकालिक योजना की परीक्षा भी है जब मौसम विभाग कई दिन पहले भारी वर्षा, लू और चक्रवात की चेतावनी जारी करता रहता है, तब स्थानीय प्रशासन समय रहते पर्याप्त तैयारी में क्यों नहीं जुट पाता है? अक्सर राहत कार्य आपदा आने के बाद शुरू होते हैं। यदि पहले से जल निकासी की व्यवस्था, सुरक्षित आश्रय, पेयजल, चिकित्सा दल और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दी जाए, तो जन-धन की हानि काफी कम की जा सकती है।

दूसरी बड़ी समस्या हमारी अनियोजित शहरीकरण की है। शहरों के तालाब, नाले और जलग्रहण क्षेत्र पाटकर भवन खड़े कर दिए गए। नदियों के प्राकृतिक मार्ग पर अतिक्रमण हुआ परिणामस्वरूप कुछ घंटों की तेज बारिश भी शहरों को जलमग्न कर देती है। दूसरी ओर वर्षा का वही पानी भूजल में नहीं समा पाता और कुछ ही महीनों बाद वही क्षेत्र जल संकट से जूझने लगता है। विडंबना यह है कि जिस पानी को बाढ़ के समय हम अभिशाप मानते हैं, उसी पानी की एक-एक बूंद के लिए गर्मियों में तरसते हैं। यदि बड़े पैमाने पर वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, तालाबों का पुनर्जीवन, चेक डैम और जल संरक्षण के कार्य निरंतर किए जाएँ तो बाढ़ का पानी भी भविष्य का अमृत बन सकता है।

जलवायु परिवर्तन ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब वर्षा कम दिनों में अधिक तीव्रता से होती है और गर्मी की अवधि अधिक लंबी तथा अधिक प्रचंड होती जा रही है। यही कारण है कि कभी तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है तो कहीं कुछ ही घंटों में महीनों जितनी वर्षा हो जाती है। विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि चरम मौसम की घटनाएँ अब नई सामान्य स्थिति बनती जा रही हैं।

इसके बावजूद हमारी अधिकांश योजनाएँ अभी भी पुराने मौसम चक्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। शहरों की जल निकासी व्यवस्था दशकों पुरानी है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के कार्य पर्याप्त नहीं हैं और नदी तटों पर निर्माण आज भी जारी है।

आपदा प्रबंधन का अर्थ केवल राहत सामग्री बाँटना नहीं है। वास्तविक आपदा प्रबंधन वह है जिसमें आपदा आने से पहले जोखिम कम कर दिया जाए। विकसित देशों में पूर्व चेतावनी, सामुदायिक प्रशिक्षण, नियमित मॉक ड्रिल, आधुनिक संचार व्यवस्था और स्थानीय स्तर पर त्वरित निर्णय प्रणाली पर विशेष बल दिया जाता है। भारत में भी इन व्यवस्थाओं को गाँव-गाँव और वार्ड स्तर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। सरकारों की जवाबदेही जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही समाज की भी। जल स्रोतों को बचाना, वृक्षारोपण करना, प्लास्टिक और कचरे से नालियाँ न भरना, वर्षा जल संचयन अपनाना तथा स्थानीय जलाशयों का संरक्षण करना नागरिकों का भी कर्तव्य है। यदि समाज और शासन मिलकर कार्य करें, तभी स्थायी समाधान संभव है।

विशेषज्ञ बार-बार यह भी कहते हैं कि हर जिले का अलग जलवायु अनुकूलन योजना तैयार होना चाहिए। जिन क्षेत्रों में सूखा अधिक पड़ता है वहाँ जल संरक्षण और सूखा-रोधी खेती को बढ़ावा मिले, जबकि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नदी प्रबंधन, तटबंधों का वैज्ञानिक रखरखाव, जल निकासी और सुरक्षित पुनर्वास की स्थायी व्यवस्था हो।

हाल के वर्षों में यह भी स्पष्ट हुआ है कि केवल राहत कोष बढ़ाने से समस्या समाप्त नहीं होगी। आवश्यकता ऐसी विकास नीति की है जिसमें सड़क, पुल, भवन, कॉलोनियाँ और औद्योगिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के जोखिमों को ध्यान में रखकर बनाए जाएँ। अस्पताल, विद्यालय, बिजली व्यवस्था और संचार तंत्र भी आपदा सहनशील होने चाहिए। अंततः प्रश्न संसाधनों का नहीं, बल्कि दूरदृष्टि, इच्छाशक्ति और प्रभावी क्रियान्वयन का है। यदि हम हर वर्ष बाढ़ और सूखे के बाद केवल नुकसान का आकलन करते रहेंगे, तो आने वाले वर्षों में यह संकट और विकराल होगा।

-संजीव ठाकुर

फिर अतिक्रमण की चपेट में नगर, अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान

चार माह पहले अधिकारियों ने दिखाई थी सख्ती, फिर पसरने लगा अतिक्रमण

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। नगर में एक बार फिर अतिक्रमण पसरने लगा है। इससे अब हाईवे भी अछूता नहीं है। जहां डिपो के पास प्रतिदिन दो से तीन बार लंबा जाम लग रहा है। करीब चार माह पहले अधिकारियों ने जो सख्ती दिखाई थी वह अब नदारद हो चुकी है जिससे लोगों का आवागमन करना मुश्किल हो गया है।

नगर के एबी रोड स्थित पुराने डिपो के पास वाले क्षेत्र में फल और सब्जी के ठेलों की वजह से लगातार जाम लग रहा है। इससे लोगों को हर दिन भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कलेक्टर सहित प्रशासन के बड़े अधिकारी दिन में कई बार इसी रास्ते से निकलते हैं, लेकिन सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लोगों ने बताया कि पहले ठेले वाले सड़क से हटकर अपनी दुकानें लगाते थे। लेकिन जब से सड़क चौड़ी करने का काम हुआ है, तब से ज्यादातर ठेले सड़क पर ही खड़े होने लगे हैं। इसके अलावा फल-सब्जी खरीदने आने वाले लोग भी अपनी मोटरसाइकिल और कारें सड़क पर ही खड़ी कर देते हैं, जिससे रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है। सोमवार दोपहर करीब तीन बजे हालात इतने बिगड़ गए कि गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और लोगों को इस जाम से निकलने में करीब 20 मिनट का समय लगा।

प्रतिदिन बिगड़ते हैं हालात, परेशान हो रहे नगरवासी- यह स्थिति केवल सोमवार की नहीं है बल्कि प्रतिदिन यहां ऐसी स्थिति बनती है जब वाहनों की लंबी कतारें लग जाती हैं। न वाहन उधर जा सकते हैं ओर न ही इधर से जा सकते हैं। बड़े वाहन के आ जाने से यहां वाहनों की कतारें लग जाती हैं। जिसे अधिकारी भी देखकर अनदेखा कर देते हैं। जिसका खामियाजा नगरवासियों को भुगतना पड़ रहा है।

आधी सड़क पर कीचड़, आधी पर ठेलों का कब्जा - इन दिनों हाईवे पर फोरलेन निर्माण का काम चल रहा है। जिससे आधी सड़क तो पहले से ही चल रहे निर्माण कार्य और कीचड़ की वजह से बंद पड़ी है और जो बाकी का हिस्सा बचता है उस पर ठेले और गाड़ियां खड़ी रहती हैं। ऐसे हालात में यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नगरवासियों ने प्रशासन से इस मामले में तुरंत कड़ा एक्शन लेने की मांग की है। लोगों ने अपील की है कि डिपो इलाके को ठेलों और गाड़ियों के अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया जाए, ताकि यहां हर दिन लगने वाले जाम से मुक्ति मिल सके और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके।

फिर याद आने लगी सख्ती- एसडीएम मनीषा वास्कले के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम द्वारा अप्रैल माह में सख्ती दिखाते हुए अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू की थी, जिससे शहर की सूरत भी संवरने लगी थी। इसके बाद अधिकारियों ने अतिक्रमण मुहिम से मुंह मोड़ लिया। नतीजा फिर नगर में सड़क पर सामान पसरने लगा और सड़कें फिर से छोटी होने लगी हैं। अतिक्रमणकारियों ने हाईवे को भी नही छोड़ा।

मानदेय वृद्धि और स्वास्थ्य बीमा की मांग

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। आशा-आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सोमवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने विधायक अरुण भीमावद को ज्ञापन देकर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम भी ज्ञापन भेजा।

संगठन ने ज्ञापन में बताया कि साल 2023 में सरकार द्वारा की गई कई घोषणाएं अब तक लागू नहीं हुई हैं, जिससे प्रदेश की करीब 84 हजार आशा एवं आशा पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। संघ की जिला अध्यक्ष मोना प्रजापति ने बताया कि ज्ञापन में आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में हर साल एक हजार रुपये की बढ़ोतरी लागू करने की मांग की गई है। इसके अलावा पर्यवेक्षकों को 15 हजार रुपए मानदेय के साथ अलग से यात्रा भत्ता देने, पांच लाख रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य व दुर्घटना बीमा करने, आकस्मिक एवं साप्ताहिक अवकाश की सुविधा देने और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार लंबित एरियर का भुगतान करने की मांग शामिल है। इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बनाने सहित अन्य गैर-विभागीय कार्यों का अतिरिक्त भार उन पर न डाला जाए। इसके साथ ही हर महीने समय पर वेतन का भुगतान करने, वेतन कटौती पर रोक लगाने, ऑनलाइन पारदर्शी प्रोत्साहन राशि व्यवस्था लागू करने और रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने की भी मांग की गई। संघ ने अधिकारियों ने मनमाने ढंग से सेवा समाप्ति और अभद्र व्यवहार पर भी रोक लगाने की मांग की है। वहीं कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी इन मांगों का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो 20 जुलाई से भोपाल में प्रदेश स्तरीय आंदोलन शुरू किया जाएगा। कार्यकर्ताओं के मुताबिक इस आंदोलन के बाद सभी आशा और सहयोगी कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए जिले में 14 जुलाई से शुरू होगा दस्तक अभियान और स्टॉप डायरिया कैम्पेन

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। देवास प्रदेश में बाल मृत्यु के मामलों में प्रभावी कमी लाने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दस्तक अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान का प्रथम चरण विशेष रणनीति के तहत दस्तक अभियान' सह स्टॉप डायरिया कैम्पेन 2026 के रूप में संचालित होगा। यह अभियान 14 जुलाई 2026 से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक चलाया जाएगा। अभियान के दौरान ए.एन.एम., आशा कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संयुक्त दल जिले के उन हर घर में दस्तक देगा, जहाँ 5 वर्ष तक की आयु के बच्चे निवास कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सरोजिनी जेम्स बेक ने बताया कि संयुक्त दल द्वारा 05 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बाल्यकालीन दस्त रोग नियंत्रण के लिए बच्चों को दो ओआरएस पैकेट एवं 14 जिंक टेबलेट दी जायेगी। 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को आयु-अनुरूप विटामिन ए का अनुपूरण। डीएसएस टूल के माध्यम से 5 वर्ष से कम आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों की सक्रिय पहचान तथा चिकित्सीय जटिल सेम बच्चों का रेफरल एवं संस्थागत उपचार, दस्त रोग, निर्जलीकरण तथा अन्य बाल्यकालीन बीमारियों से ग्रसित बच्चों की पहचान, प्रोटोकॉल अनुसार उपचार व रैफरल कर प्रबंधन किया जायेगा। स्टॉप डायरिया केम्पैन-2026 अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं गामीण विकास, नगरीय शासन एवं विकास, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी एवं स्कूल शिक्षा विभाग से समन्वय स्थापित किया जाएगा। स्टॉप डायरिया कैंपेन का उद्देश्य बाल्य कालीन दस्त रोग में जिंक एवं ओआरएस. के उपयोग को बढ़ावा देना एवं उच्च कवरेज सुनिश्चित करना, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में दस्त की रोकथाम और प्रबंधन के लिए जागरूकता बढ़ाना हैं।

लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण पर कलेक्टर का जोर

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आवेदनों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा शासन द्वारा संचालित अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिटर, सांसद, प्रभारी मंत्री एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त लंबित आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर देते हुए विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

ट्रांसफर रूकवाने बच्चों का किया इस्तेमाल, खुल गई पोल

जिला शिक्षा अधिकारी करेंगी मामले की जांच, दोषी पाए जाने पर संबंधितों के खिलाफ होगी कार्रवाई

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। एक शिक्षक ने अपना ट्रांसफर रूकवाने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया जो उन्हें गांव से बैठाकर सीधे डीईओ कार्यालय ले गए। हालांकि शिक्षक की यह ट्रिक काम नहीं आई और उनका काम अटक गया। अब शिक्षक का यह मामला तो अटक गया और बात जांच पर आ गई। यदि जांच में शिक्षक द्वारा बच्चों का इस्तेमाल करने की बात साबित होती है तो शिक्षक का ट्रांसफर तो होगा ही। वहीं उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।

दरअसल शिक्षा विभाग में सोमवार को मेहंदी गांव के 10 से 15 छोटे छात्र जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कार्यालय पहुंच गए। इन बच्चों की उम्र लगभग 5 से 10 वर्ष बताई जा रही है। वे शिक्षक अरशदुल्लाह पठान का कालापीपल तबादला रद्द करने की मांग कर रहे थे। यही नहीं इन विद्यार्थियों ने स्कूल के प्राचार्य नरेश उगले पर मारपीट करने और उनसे छोटे-मोटे काम कराने के भी आरोप लगाए। इस घटना के बाद पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

मैडम से क्या कहना है- मामला उस समय और संदेहास्पद हो गया जब जिला शिक्षा अधिकारी के आने से पहले शिक्षक अरशदुल्लाह पठान बच्चों से बातचीत करते दिखाई दिए। वे बच्चों से पूछ रहे थे कि मैडम के सामने क्या कहना है। लेकिन जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी दीपा किर वहां पहुंचीं बच्चे भी चुप हो गए और बातचीत भी रुक गई और बच्चे शांत हो गए। इस पर अधिकारी को शक हो गया और मामला पूरी तरह पलट गया।

14 किलोमीटर दूर से लेकर आया बच्चों को- मेहंदी गांव जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर दूर है। स्कूल में कुल 41 विद्यार्थी और 6 शिक्षक पदस्थ हैं। इनमें प्राचार्य नरेश उगले का तबादला शाजापुर तथा शिक्षक अरशदुल्लाह पठान का स्थानांतरण कालापीपल हो चुका है। ऐसे में केवल 10 से 15 बच्चों का जिला मुख्यालय पहुंचकर शिकायत करना कई सवाल खड़े कर रहा है। यह स्पष्ट नहीं है कि बच्चे अपनी पहल पर पहुंचे थे या किसी के मार्गदर्शन में।

बच्चे पहुंचे स्कूल, शिक्षक ले आया शाजापुर- खास बात यह है कि बच्चे घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकले थे, लेकिन वे ऑटो रिक्शा से जिला शिक्षा कार्यालय पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि न तो स्कूल प्रबंधन और न ही प्राचार्य यह स्पष्ट कर सके कि बच्चों को वहां कौन लेकर आया। बच्चे शिक्षक अरशदुल्लाह पठान का तबादला रुकवाने और प्राचार्य की शिकायत करने पहुंचे थे। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि इतनी कम उम्र के बच्चे स्वयं इस तरह शिकायत की प्रक्रिया तक कैसे पहुंचे। पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

इनका कहना है- बच्चों को किसी ने समझाकर भेजा है ताकि शिक्षक का तबादला रुकवाया जा सके। रही बात मुझ पर लगाए गए आरोप की तो वे निराधार है।

- नरेश उगले, प्राचार्य

छात्रों की शिकायतों के साथ-साथ पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। यदि मारपीट के आरोप सही पाए जाते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होगी और यदि जांच में यह सामने आता है कि तबादला प्रभावित करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल किया गया, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- दीपा किर, जिला शिक्षा अधिकारी-शाजापुर

मंदिर से चुराए बर्तन, व्यापार की सजगता से खुली पोल

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। लालघाटी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी मंदिरों से चोरी किए गए पीतल और तांबे के पूजा-पाठ के सामान बेचने एक दुकान पर पहुंचा था। दुकानदार को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो बदमाश को हिरासत में लिया जिसे बाद में चेतावनी देकर छोड़ दिया। लालघाटी थाना प्रभारी अर्जुन सिंह मुजाल्दे ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने तराना क्षेत्र के मंदिरों से पीतल और तांबे के लोटे, थालियां, कटोरियां और गिलास सहित अन्य सामान चोरी करना स्वीकार किया। आरोपी की पहचान बरोठिया निवासी भगवान पिता नारायण परमार (33) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी की एक डिस्कवर मोटरसाइकिल और मंदिरों से चोरी किया गया करीब 20 हजार रुपये मूल्य का तांबे व पीतल का सामान जब्त किया है। बरामद सामग्री में लोटे, प्लेट, कटोरियां, गिलास और अन्य पूजा सामग्री शामिल है। फिलहाल लालघाटी पुलिस ने आरोपी को नोटिस देकर छोड़ दिया है।

लायंस क्लब ऑफ देवास सिटी की नवीन कार्यकारिणी घोषित

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। लायंस क्लब ऑफ देवास सिटी की नॉमिनेशन कमेटी द्वारा वर्ष 2026-27 की कार्यकारिणी का मनोनयन सर्वसम्मति से किया गया। उक्त कार्यकारिणी में अध्यक्ष लायन अनिल नागर, सचिव लायन प्रमोद गुप्ता, कोषाध्यक्ष लायन एम.एल. डाबी को नियुक्त किया गया।

?साथ ही प्रशासनिक उपाध्यक्ष लायन भगवान गोयल, सेवा गतिविधि उपाध्यक्ष लायन दिनेश माहेश्वरी, पी.आर.ओ. लायन आर.सी. पालीवाल, टेमर-लायन विशाल अग्रवाल एवं संचालक लायन अशोक जोशी, लायन एम.के. नागर, लायन रमेश व्यास, लायन रेणु शर्मा, लायन करुणा सोनी को मनोनीत किया गया।

लायंस क्लब ऑफ देवास सिटी कई सामाजिक गतिविधियों को संचालित करती है एवं वर्ष 2026-27 में भी पीड़ित मानव सेवा का यह सिलसिला जारी रहेगा। सभी नव मनोनीत पदाधिकारियों को क्लब के रिजन पर्सन लायन ओसाफ कुरैशी, लायन डॉ. के.के. धूत, लायन डॉ. आर.सी. शर्मा, लायन एम.एल. अग्रवाल, लायन एस.के. गुप्ता, लायन डॉ. प्रकाश गर्ग, लायन डॉ. योगेश वालिम्ब, लायन राधेश्याम सोनी, लायन सुरेश परवाल, लायन डॉ. जे.एस. यादव, लायन प्रहलाद अग्रवाल, लायन एस.के. अग्निहोत्री, लायन राजेश शास्त्री व निवर्तमान अध्यक्ष मनोज बिंदल द्वारा बधाई दी गई एवं हर्ष व्यक्त किया।

हाईवे पर पलटी प्याज से भरी ट्राली

शाजापुर/दैनिक मालवा हेराल्ड। सनकोटा बायपास पर सोमवार सुबह करीब 6.30 बजे प्याज से भरी एक ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर पर सवार दोनों लोग सुरक्षित बच गए। बताया जाता है कि उतरते समय निर्माणाधीन सड़क पर पड़े पत्थर से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ये हादसा हो गया और ट्राली में रखी प्याज की बोरियां सड़क पर बिखर गई, जिससे कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। ग्राम सामगी निवासी महादेव गोठी और संग्राम गोठी निवासी कनार्दी ट्रैक्टर-ट्राली में प्याज भरकर शाजापुर मंडी बेचने के लिए आ रहे थे। हादसे के समय दोनों ट्रैक्टर पर ही सवार थे। गनीमत रही कि वे बाल-बाल बच गए और किसी को गंभीर चोट नहीं आई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना की सूचना मिलते ही लालघाटी डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। आरक्षक जितेंद्र मालवीय और पायलट कमलेश ने तत्काल मोर्चा संभालते हुए यातायात को व्यवस्थित कराया और दुर्घटनास्थल को सुरक्षित किया। इसके बाद सड़क पर बिखरी प्याज की बोरियों को हटाने की व्यवस्था की गई, जिससे मार्ग पर आवागमन सामान्य हो सका।

किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान पर कलेक्टर का जोर, किसान संघ के प्रतिनिधियों से किया संवाद

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। किसानों को खाद, बिजली, सिंचाई, फसल बीमा तथा समर्थन मूल्य पर उपज विक्रय से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित बेतवा सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ऊर्जा, कृषि, जल संसाधन तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

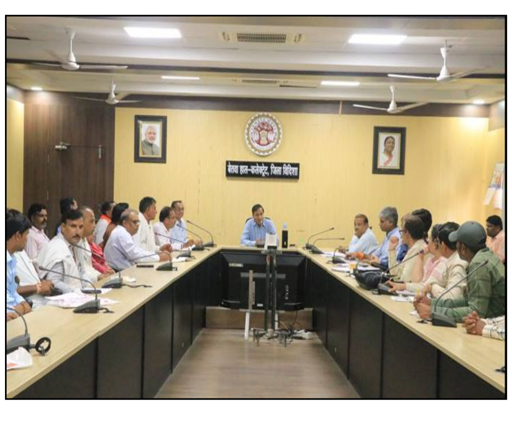

बैठक में किसानों द्वारा खाद की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, सिंचाई सुविधाओं, फसल बीमा दावों के निराकरण तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी से संबंधित समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए, जिससे उन्हें खेती-किसानी के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने किसानों से अपील की है कि वे मिट्टी परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर ही संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक पद्धति से उर्वरक प्रयोग करने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, उत्पादन लागत कम होती है तथा फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में वृद्धि होती है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मिट्टी परीक्षण के परिणामों के अनुरूप उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए।

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जिले में खाद वितरण , सिंचाई व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति और समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी की तैयारियों की लगातार निगरानी की जा रही है।

कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर किसानों को समय पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए , ताकि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। डीएपी खाद आपूर्ति के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया है। किसान संघ के प्रतिनिधि को बताया गया कि प्रदेश में सबसे ज्यादा डीएपी पूर्ति विदिशा जिले में अब तक की गई है। बैठक में डीएपी के वैकल्पिक व्यवस्था, नैनो डीएपी का उपयोग करने की सलाह दी गई है।

कलेक्टर श्री गुप्ता ने किसानों से अहवान किया है कि कृषि क्षेत्रों में हो रहे नवाचारों का अधिकार से अधिक जिले के कृषक बंधु उपयोग कर जिले की ख्याति में वृद्धि करें ताकि अन्य किसानों को प्रेरणा मिल सकें।

किसने इन बिंदुओं से कराया अवगत - बैठक में भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी समस्याओं से संबंधित विभिन्न बिंदुओं से अवगत कराया जिनमें सीमांकन, गलत सीमांकन के चलते हो रही परेशानियां, पटवारी नक्शा एवं सैटेलाइट नक्शा का सही मिलान जब तक ना हो रोवर, ईटीएसएम मशीन से सीमांकन करने पर शीघ्र रोक लगाकर जरीब से सीमांकन करने। बीमा खरीफ 2025 में अति वृष्टि के कारण बर्बाद फसल का मुआवजा दिलाने, राजस्व विभाग में रजिस्ट्री के बाद समय सीमा में नामांतरण करने, मूंग ग्रीष्मकालीन मूंग की शत-प्रतिशत खरीदी करने, जिले की सभी मंडियों में मंडी बोर्ड के आदेश 26 जून 2020 का पालन करते हुए बीओटी (धर्म कांटे) से तुलाई कराने, आकाशीय बिजली से ग्राम करैया तहसील शमशाबाद निवासी लाखन सिंह बंजारा की मृत्यु 23 जून 2026 को हुई थी मृतक के परिवार को शीघ्र आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने सहित अन्य समस्याएं शामिल रहीं।

लंबित आवेदनों के त्वरित निराकरण पर कलेक्टर का जोर, स्कूलों में फर्नीचर व मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा

विदिशा/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के बेतवा सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों के लंबित आवेदनों, जनकल्याणकारी योजनाओं तथा शासन द्वारा संचालित अभियानों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने विशेष रूप से सीएम हेल्पलाइन, सीएम मॉनिटर, सांसद, प्रभारी मंत्री एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयों से प्राप्त लंबित आवेदनों के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर जोर देते हुए विभागीय अधिकारियों को समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की जानकारी अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने कहा कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और संतोषजनक निराकरण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने सभी विभागों को जनहित से जुड़े मामलों में गंभीरता और जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जनहितैषी योजनाओं एवं अभियानों की अद्यतन प्रगति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री गुप्ता ने निर्देश दिए कि जिले के सभी शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में शत-प्रतिशत विद्यार्थियों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाए तथा उनकी नियमित उपस्थिति दर्ज हो। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें, साइकिल, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र आईडी सहित शासन द्वारा प्रदाय सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं।

आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों ने वेतन, बकाया भुगतान और 1000 रूपये वार्षिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

देवास/ राजेन्द्र सिंह पंवार/ दैनिक मालवा हेराल्ड। म.प्र. आशा/आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के बैनर तले प्रदेश आव्हान पर देवास जिला मुख्यालय पर आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों ने अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया तथा मुख्यमंत्री एवं मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाम संघ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनुराधा लोधी की उपस्थिति में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष सुनीता चौहान एवं संगठन मंत्री अनिता सिंह ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को प्रोत्साहन राशि (वेतन) का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा है। कई-कई महीनों तक वेतन लंबित रखा जाता है तथा भुगतान में पारदर्शिता का अभाव है। कर्मचारियों को यह जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई जाती कि उन्हें कितनी राशि का भुगतान किया गया है और कितनी राशि बकाया है। संघ का कहना है कि वर्ष 2023 में सरकार द्वारा घोषित ?1000 की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ आज तक आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों को नहीं दिया गया, जबकि अन्य वर्गों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। संगठन ने वर्ष 2024 से इस वार्षिक वेतन वृद्धि का एरियर सहित भुगतान करने की मांग की है। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि आशा कार्यकर्ताओं को मात्र ?6000 मासिक मानदेय में कठिन परिस्थितियों में चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवाएं देनी पड़ती हैं। वहीं आशा पर्यवेक्षकों को भी निर्धारित वेतन के बावजूद यात्रा व्यय स्वयं वहन करना पड़ रहा है।

संगठन ने आरोप लगाया कि साप्ताहिक एवं शासकीय अवकाश के नाम पर वेतन कटौती की जाती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। संघ ने अधिकारियों द्वारा आयुष्मान कार्ड सहित अन्य गैर-विभागीय कार्य कराने तथा कई मामलों में अपने निजी खर्च से कार्य करवाने के लिए दबाव बनाने का भी आरोप लगाया। साथ ही बिना जांच के वेतन कटौती एवं सेवा समाप्ति जैसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई। ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख मांगों में प्रत्येक माह की 5 तारीख तक बिना कटौती नियमित वेतन भुगतान, वेतन पर्ची उपलब्ध कराना, ?1000 वार्षिक वेतन वृद्धि का एरियर सहित भुगतान, पर्याप्त बजट की व्यवस्था, गैर-विभागीय कार्यों के लिए अतिरिक्त भुगतान, आशा कार्यकर्ताओं को ?26,000 तथा पर्यवेक्षकों को ?35,000 न्यूनतम वेतन, पृथक यात्रा भत्ता, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति, टीम आधारित इंसेंटिव, शासकीय अस्पतालों के निजीकरण पर रोक, सम्मानजनक कार्य वातावरण तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लंबित राशि का भुगतान शामिल हैं। संघ ने चेतावनी दी कि यदि आशा एवं आशा पर्यवेक्षकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो प्रदेशभर में आंदोलन को और अधिक व्यापक रूप दिया जाएगा। इस दौरान विमल घावरी, रेखा सोलंकी, सीता ग्रेवाल, सविता चौहान, माया परिते, वर्षा दरबार दीप सिखा, पवित्रा चौहान, जरीना, संगीता पांडे, भागवंता, आशा परमार, राज कुंवर, रीना मालवीय, जसोदा, कमलेश लोधी, आशा भार्गव, रेखा जोशी, ममता यादव, संगीता घुनावत, मंजू चौहान सहित बड़ी संख्या में आशाएं उपस्थित थी।

भाटपचलाना पुलिस की त्वरित कार्रवाई, छेड़छाड़ के आरोपी को एक घंटे में दबोचा

मूक-बधिर युवती से दुष्कर्म की कोशिश पर सख्त एक्शन, आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। भाटपचलाना पुलिस ने एक बार फिर अपनी तत्परता और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए महिला अपराध के एक गंभीर मामले में सराहनीय कार्रवाई की है। मूक-बधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने महज एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया।

पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करणदीप सिंह तथा अनुविभागीय अधिकारी पुलिस आकांक्षा बेछोटे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सतेन्द्र सिंह चौधरी एवं उनकी टीम ने यह त्वरित कार्रवाई करते हुए अपराधी को तुरंत कानून के शिकंजे में ले लिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बालोदा लक्खा निवासी एक युवक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 21 वर्षीय बहन, जो मूक-बधिर एवं मानसिक रूप से कमजोर है, घर में अकेली थी। इसी दौरान आरोपी मांगीलाल घर में घुस आया और उसके साथ गलत हरकत करने लगा।

सूचना मिलते ही भाटपचलाना पुलिस ने बिना देरी किए मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाई और घटना के एक घंटे के भीतर ही आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

सराहनीय भूमिका- इस सफल कार्रवाई में थाना प्रभारी सतेन्द्र सिंह चौधरी, उपनिरीक्षक मोनिका तिवारी, आरक्षक जीवन जाट, हितेश निम्बोला, मुकेश नागर तथा महिला आरक्षक मोनिका राव की विशेष भूमिका रही।

भाटपचलाना पुलिस की इस त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से पीड़ित परिवार को त्वरित न्याय मिला है, वहीं गांव में पुलिस के प्रति विश्वास और सुरक्षा की भावना भी मजबूत हुई है।

वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उदय अपनी होते हुए सेवानिवृत

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बड़नगर द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी उदय कुमार अग्निहोत्री के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में गरिमामय सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, परिजनों एवं गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उनके दीर्घ, उत्कृष्ट एवं कृषक हित में समर्पित सेवाकाल की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष कृषि विकास अधिकारी संघ मनोहर गिरी रहे। विशिष्ट अतिथियों में सहायक संचालक कृषि कमलेश कुमार राठौर (उज्जैन), कृषि समिति अध्यक्ष राजाराम डाबी, कृषि समिति सदस्य टीकम सिंह एवं जुझार सिंह, भाजपा नेता हरि किशन मेलवानी ,देवी दास मूलचंदानी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने श्री अग्निहोत्री के सेवाकाल को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सादगी एवं किसानों के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण बताते हुए उनके स्वस्थ, सुखमय एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामनाएँ दीं।

समारोह का संचालन कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष अंकुश गुप्ता ने किया। प्रारंभ में चेतन पटेल ने स्वागत भाषण देकर सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। अंत में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार सोलंकी ने आभार व्यक्त करते हुए श्री अग्निहोत्री के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली को विभाग के लिए प्रेरणादायी बताया।

इस अवसर पर सेवानिवृत्त उदय कुमार अग्निहोत्री का शॉल, श्रीफल, पुष्पहार एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने सेवाकाल में किसानों की समस्याओं के समाधान, कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागीय दायित्वों के निर्वहन में सदैव संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं कर्मनिष्ठा का परिचय दिया। उनका सहज, सरल और सहयोगी व्यक्तित्व लंबे समय तक सभी के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

खेतों में पर्याप्त नमी के बाद ही करें बोवाई

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मौसम की अनिश्चितता के बारे में लगाए जा रहे अनुमानों के बाद भी किसान भाईयों को चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। खरीफ की बुआई के लिए कुछ सावधानियां अपनाकर किसान उत्पादन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। कुछ जिलों में अल्प वर्षा को देखते हुए खरीफ फसलों की बोवाई में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तक खेतों में पर्याप्त नमी न हो जाए, तब तक बुआई करना जोखिम पूर्ण हो सकता है। कृषक कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने वैज्ञानिकों के परामर्श से किसानों को सलाह दी है। संचालक कृषि श्री उमाशंकर भार्गव ने इस संबंध में मैदानी अमले को किसानों से सतत संपर्क करने के अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। सामान्य रूप से 4 इंच यानि लगभग 1 बालिश्त की गहराई तक नमी होने तथा बतर आने के बाद बोवाई की आदर्श स्थिति मानी जाती है। वर्तमान में पूरी तरह मानसून की सक्रियता न होने के कारण बोवाई के लिए किसानों को प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की पर्याप्तता हो उन्हें मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिये ढैंचा या सनई की बुवाई हरित खाद के रूप में करना चाहिये। जिन क्षेत्रों में पूर्व में वर्षा हुई है, वे भी हरित खाद या ग्रीन मैन्योरिंग हेतु फसलें बो सकते हैं। बुवाई के लिए तैयार खेतों में आधार खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कम्पोस्ट एवं उर्वरक जैसे सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और जिंक सल्फेट तथा जिप्सम आदि को खेत में बोवाई या छिड़काव द्वारा मिलाया जा सकता है।

कृषि सलाह के अनुसार किसान भाई, सोयाबीन के बीज का अंकुरण परीक्षण कर 70 प्रतिशत से अधिक अंकुरण क्षमता वाले बीजों का उपयोग करें। रोग एवं कीट प्रतिरोधी उपयुक्त ऐसी किस्मों का चयन करें जिनकी जल मांग भी कम हो। इसके लिये कृषि अधिकारियों से परामर्श लेना उपयोगी होगा। बुवाई से पूर्व बीजों को फफूंदनाशकों एवं जैव उर्वरकों से उपचारित करना आवश्यक है।

सोयाबीन फसल की बुवाई में जलभराव एवं सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने हेतु रिज- एंड फरो सीड ड्रिल, ब्रॉड बेड एंड फरो सीड ड्रिल अथवा हस्तचालित सीड डिब्लर का प्रयोग करना उपयोगी है। इसी प्रकार धान की बोवाई के लिए श्री पद्धति अथवा सीधी बोवाई अपनाना लाभकारी है।

निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया प्रारंभ

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रदेश में शिक्षा का अधिकार कानून अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी स्कूलों में निश्शुल्क प्रवेश के लिए तीसरे चरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके अंतर्गत 8 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र, स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक को निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1) (ग) के अंतर्गत पात्र बच्चों को अशासकीय, गैर-अनुदान प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है, जिसका शुल्क प्रदेश सरकार वहन करती है। प्रदेश में आरटीई के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया के बाद जिन विद्यालयों में सीटें रिक्त रह गई हैं, उन सभी विद्यालयों को उनकी रिक्त सीटों सहित द्वितीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।

तीसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं होगा- राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री हरजिंदर सिंह ने बताया कि तृतीय चरण की प्रवेश प्रक्रिया में कोई नया पंजीयन नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए केवल उन्हीं आवेदकों को शामिल किया जाएगा, जिन्होंने पहले चरण में आवेदन किया था। ऐसे आवेदक, जिन्होंने पूर्व चरणों में आवेदन किया था और सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए, लेकिन उन्हें कोई भी विद्यालय आवंटित नहीं हुआ, वे तृतीय चरण के लिए विद्यालयों की चॉइस अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा, जिन आवेदकों को पूर्व चरण में विद्यालय आवंटित हुआ था, लेकिन विद्यालय पसंद न आने या अन्य कारणों से उन्होंने प्रवेश नहीं लिया, वे भी तृतीय चरण की प्रक्रिया में शामिल होकर अपनी पसंद के अनुसार विद्यालयों की चॉइस फिर से अपडेट कर सकेंगे।

प्रवेश प्रक्रिया की समय सारिणी- 08 जुलाई 2026 तक- आवेदकों को रिक्त सीटों वाले विद्यालयों के लिए अपनी चॉइस अपडेट करने होगी। 10 जुलाई 2026- तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन लॉटरी 11 से 20 जुलाई 2026-आवंटन के बाद संबंधित विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया एवं संबंधित विद्यालय द्वारा आरटीई मोबाइल ऐप के माध्यम से जानकारी दर्ज की जाएगी।

कर्तव्यनिष्ठ सेवाओं को मिला सम्मान, चार दशक की समर्पित सेवा के बाद सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त अग्निहोत्री

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बड़नगर द्वारा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री उदय कुमार अग्निहोत्री के सेवानिवृत्ति उपलक्ष्य में गरिमामय सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों, परिजनों एवं गणमान्य नागरिकों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर उनके दीर्घ, उत्कृष्ट एवं कृषक हित में समर्पित सेवाकाल की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष कृषि विकास अधिकारी संघ श्री मनोहर गिरी रहे। विशिष्ट अतिथियों में सहायक संचालक कृषि श्री कमलेश कुमार राठौर (उज्जैन), कृषि समिति अध्यक्ष श्री राजाराम डाबी, कृषि समिति सदस्य श्री टीकम सिंह एवं श्री जुझार सिंह, भाजपा नेता श्री हरि किशन मेलवानी ,श्री देवी दास मूलचंदानी जी उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने श्री अग्निहोत्री के सेवाकाल को ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सादगी एवं किसानों के प्रति समर्पण का अनुपम उदाहरण बताते हुए उनके स्वस्थ, सुखमय एवं यशस्वी जीवन की मंगलकामनाएँ दीं।

समारोह का संचालन कृषि विस्तार अधिकारी संघ के जिला अध्यक्ष श्री अंकुश गुप्ता ने किया। प्रारंभ में श्री चेतन पटेल ने स्वागत भाषण देकर सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। अंत में वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार सोलंकी ने आभार व्यक्त करते हुए श्री अग्निहोत्री के व्यक्तित्व एवं कार्यशैली को विभाग के लिए प्रेरणादायी बताया।

इस अवसर पर श्री उदय कुमार अग्निहोत्री का शॉल, श्रीफल, पुष्पहार एवं स्मृति-चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। वक्ताओं ने कहा कि उन्होंने अपने सेवाकाल में किसानों की समस्याओं के समाधान, कृषि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा विभागीय दायित्वों के निर्वहन में सदैव संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं कर्मनिष्ठा का परिचय दिया। उनका सहज, सरल और सहयोगी व्यक्तित्व लंबे समय तक सभी के लिए प्रेरणा बना रहेगा।

समारोह में विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी श्री दशरथ पोपंडिया, श्री चंदन पटेल, श्री नारायण पाटीदार, श्री संदीप कवलिया, श्री राम वाघेला, श्री दीपक औसारी, श्रीमती पूजा जाजमे, श्रीमती मनीषा मोरे, श्रीमती श्रद्धा कोचले, श्री रमेश डांगी सहित कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, विकासखंड बड़नगर के समस्त अधिकारी-कर्मचारी एवं श्री अग्निहोत्री के परिजन उपस्थित रहे। सम्मान, आत्मीयता और भावनाओं से ओत-प्रोत वातावरण में सम्पन्न हुए इस समारोह में सभी ने श्री उदय कुमार अग्निहोत्री के स्वस्थ, सुखद एवं यशस्वी भविष्य की कामना की।

'आदेशों की धज्जियां, किसान की जमीन पर 'राजस्व खेल'! बालोदा लक्खा में सीमांकन बना मजाक'

तहसीलदार के दो-दो आदेश फेल, राजस्व टीम ने मौके पर की सिर्फ खानापूर्ति – किसान न्याय को तरसा

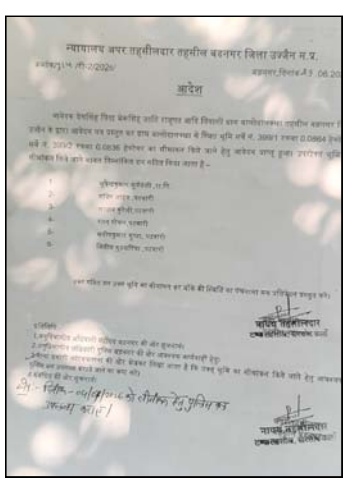

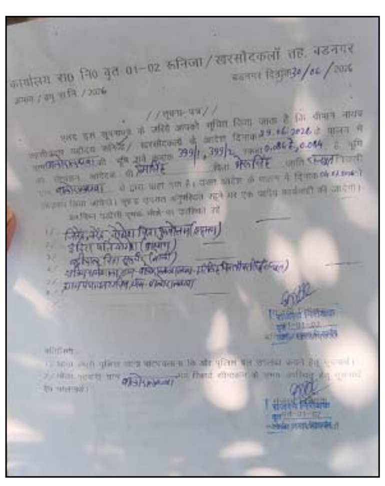

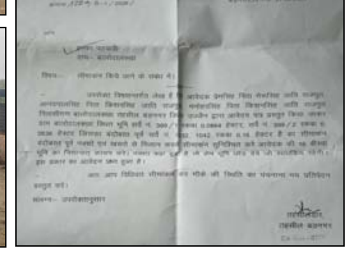

बड़नगर/ महेश सोनगरा/ दैनिक मालावा हेराल्ड। तहसील के ग्राम बालोदा लक्खा में राजस्व विभाग की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। यहां एक पीड़ित किसान प्रेम सिंह चावड़ा अपनी ही खरीदी हुई जमीन के सीमांकन के लिए महीनों से चक्कर काट रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी मानो आंख मूंदकर बैठे हैं।

तहसीलदार रुपाली जैन और नायब तहसीलदार पूनम सिंह बघेल के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, राजस्व निरीक्षक और पटवारी की गठित टीम ने आदेशों को कागज का टुकड़ा समझकर हवा में उड़ा दिया।

मौके पर पहुंची टीम ने क्या किया?

बस एक जरीब डाली इधर-उधर देखा और कह दिया – नक्शा बिगड़ा हुआ है!

और फिर पूरा सीमांकन छोड़कर लौट गए! और बहाना क्या बनाया गया?

पुलिस बल नहीं है- जबकि हकीकत ये रही कि कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई – लेकिन फिर भी सीमांकन नहीं किया गया।

सबसे बड़ा सवाल- जब किसान खुद 17 में से सिर्फ 16 बिस्वा जमीन का सीमांकन मांग रहा है, तो फिर राजस्व विभाग को आखिर दिक्कत क्या है?

कानून की समझ या जानबूझकर टालमटोल?

नियम साफ कहते हैं – बड़े रकबे में से छोटे हिस्से का सीमांकन आसानी से किया जा सकता है।

लेकिन यहां तो नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ बहानेबाजी की गई।

पीड़ित की पीड़ा

2008 से खरीदी गई जमीन का हक पाने के लिए आज भी भटक रहा है और अधिकारी?

फाइलों में आदेश लिखकर जमीनी हकीकत से मुंह मोड़ रहे हैं!

क्या राजस्व विभाग में आदेशों की कोई कीमत नहीं बची?

क्या पटवारी और राजस्व निरीक्षक अब तहसीलदार के भी ऊपर हो गए हैं?

या फिर ये पूरा खेल किसी और इशारे पर खेला जा रहा है? जब आदेश बेअसर और जिम्मेदार बेपरवाह हों तो न्याय सिर्फ कागजों में रह जाता है!

नगर में सुख शांति के लिए पंच धाकड़ समाज द्वारा नगर देवता पूजन किया गया

उन्हेल/ निर्मल आर सोलंकी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। उन्हेल पंच धाकड़ समाज द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी नगर में अच्छी वर्षा व सुख शांति बनी रहे इसके लिए समाज द्वारा नगर देवता का पूजन किया गया जिसमें श्री राम मंदिर पर समाजन एकत्रित होकर अविनाश जी उपाध्याय द्वारा पूजन करके निकले नगर के जितने भी प्रमुख मंदिर है मंदिरों पर जाकर चोला चढ़ाया वह पुष्प चढ़ा कर भगवान से आशीर्वाद लिया व प्रार्थना की की नगर में अच्छी वर्षा हो समस्त प्रकार की बीमारि से दूर रहे व नगर में सुख शांति बनी रहे धाकड़ समाज जो नगर का बडा समाज है इस लिए प्रतिवर्ष नगर देवता का पूजन करता है और सभी समाज एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर रहे सुख शांति वह समृद्धि बनी रहे जिसको लेकर कई वर्षों से यह कार्य करता आ रहा है नगर पूजन के बाद भंडारे का भी आयोजन हुआ जिसमें समाज बंधु व मंदिरों से महिला भक्त मंडल की महिलाओं ने भी प्रसादी पाई इस अवसर पर पंच धाकड़ समाज अध्यक्ष रामगोपाल मदारिया सतीश नरवाडीया गोविंद सलित्रा भेरूलाल बगड़ दिनेश पटेल हीरालाल ढोढरिया जगदीश सेकवड़िया गणेश मंडावलिया प्रकाश नयमा पूनमचंद खामोरिया जवाहरलाल धाकड़ बाबूलाल खामोरिया ओमप्रकाश सलित्रा मांगीलाल सलित्रा दिनेश नदेडा नंदराम बंबोरिया गोपाल पटेल लखन पटेल राम गोपाल वाक्तालिया राजेश एल्या गोपाल बंबोरिया ओमप्रकाश नदेडा संजय नयमा रमेशचंद बंबोरिया कैलाश सेकवाडीया गोपाल नदेडा अशोक सगीतरा बाबूलाल मदारिया श्याम सलित्रा व कई समाज बंधु उपस्थित रहे।

सिद्धिविनायक गणेश जी मंदिर पर ध्वज चढ़ाया

उन्हेल/ निर्मल आर सोलंकी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सिद्धिविनायक धाकड़ समाज धर्मशाला में पिछले वर्ष श्री सिद्धिविनायक गणेश जी मंदिर बना था जिसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बड़ा महायज्ञ किया गया था इसके पश्चात मंदिर पर ध्वज चढ़ाया था पुनः एक वर्ष बाद फिर नया ध्वज चढ़ाने को लेकर समाज द्वारा चर्चा की गई और सिद्धिविनायक गणेश जी मंदिर ध्वज चढ़ाने के लिए श्री राम मंदिर से डॉ अविनाश जी उपाध्याय द्वारा ध्वज का वेदों मंत्र उपचार के साथ में पूजन कर भव्य चल समारोह के रूप में समाज जनध्वज लेकर पहुंचे जहां सुबह से ही सिद्धिविनायक गणेश जी मंदिर पर गणेश जी का अभिषेक चल रहा था अभिषेक के पश्चात एक कुंडय हवन करवा कर सिद्धिविनायक गणेश जी मंदिर पर ध्वज चढ़ाया गया ध्वज चढ़ाने के बाद महा आरती का आयोजन हुआ आरती के पश्चात मोतीचूर के लड्डू की प्रसाद का वितरण भी किया ध्वज के मुख्य यजमान जगदीश सेकवाडिया परिवार व गोविंद सलित्रा परिवार रहे ध्वज के चल समारोह में समाज बंधु व महिला मंडल की महिलाएं भी सम्मिलित हुए।

कानवन पुलिस की बड़ी सफलता, इंदौर से बरामद की गई अपहृत नाबालिग, 3,000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार

बदनावर/ मनीष शर्मा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन मुस्कान के तहत कानवन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना कानवन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए एक नाबालिग बालिका को आरोपी के चंगुल से छुड़ाकर सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में ?3,000 के इनामी आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, घटना बीती 28 मार्च 2026 की है, जब एक अज्ञात आरोपी नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था। इसके बाद 29 मार्च 2026 को पीड़िता के पिता लाखनसिंह निवासी ग्राम मुरडका की रिपोर्ट पर कानवन थाने में अपराध क्रमांक 121/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (ब्हृस) की धारा 137(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

मामले की गंभीरता को देखते हुए धार पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारुल वेलापुरकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डाबर एवं एसडीओपी बदनावर अरविन्द तोमर के कुशल निर्देशन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। कानवन थाना प्रभारी रविन्द्र कुमार बारिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया। सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने 5 जुलाई 2026 को इंदौर जिले के थाना क्षेत्र देपालपुर से नाबालिग बालिका को आरोपी के कब्जे से सकुशल बरामद कर लिया। कागजी कार्रवाई के बाद पीड़िता को उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने नाबालिग का अपहरण करने वाले आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम आकाश पिता कैलाश वर्मा उम्र 25 साल, निवासी ग्राम अटाईडा, थाना देपालपुर, जिला इंदौर है। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक द्वारा तीन हजार रुपये के नकद इनाम की घोषणा की गई थी। पुलिस आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है।

इस चुनौतीपूर्ण मामले को सुलझाने और बालिका को सुरक्षित वापस लाने में कानवन थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र बारिया, उपनिरीक्षक कमल किशोर चौहान, आरक्षक नवीन कुमार राठौड़, आरक्षक भगवतीलाल एवं आरक्षक अजयपाल राठौर की मुख्य भूमिका रही। इसके साथ ही साइबर शाखा प्रभारी उनि प्रशांत गुंजाल, आरक्षक प्रशांतसिंह चौहान और आरक्षक शुभम शर्मा ने भी तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए सराहनीय कार्य किया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कानवन पुलिस लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में 6 जुलाई 2026 को ऑपरेशन मुस्कान के तहत इस पूरी कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समयावधि पत्रों एवं अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित

जिले में तैयार किए जा रहे हैं सिकल मित्र, ग्राम पंचायतों में अनियमितता पर होगी सख्त कार्रवाई, सामाजिक ऑडिटर भी होंगे जिम्मेदार

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर डॉ. योगेश तुकाराम भरसट की अध्यक्षता में कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में समयावधि पत्रों एवं अन्तर्विभागीय समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, लंबित प्रकरणों एवं शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष जोर देते हुए कहा कि शिकायतों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन के लेवल-1 पर लंबित 1392 शिकायतों की विभागवार समीक्षा की तथा अधिकारियों को आगामी एक सप्ताह के लिए लक्ष्य निर्धारित कर समयसीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही 11 शिकायतों के नॉन-अटेंडेड पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समीक्षा के दौरान बताया गया कि विगत एक माह में कुल 39,287 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 29,780 आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण किया गया है। कलेक्टर ने शेष लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्राम पंचायतों में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित दोषी व्यक्तियों के साथ-साथ ग्राम सामाजिक ऑडिटर के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के निर्देश दिए गए। पोषण वाटिकाओं की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए कलेक्टर ने बताया कि 293 स्वीकृत पोषण वाटिकाओं में से केवल 62 का निर्माण पूर्ण हुआ है, जो संतोषजनक नहीं है। उन्होंने शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि कुल 730 स्वीकृत भवनों में से 112 पूर्ण, 353 निर्माणाधीन तथा 14 कार्य अप्रारंभ हैं। कलेक्टर ने सभी लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने आगामी समय में विद्यालय निरीक्षण प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए विशेष मोबाइल एप विकसित करने के निर्देश दिए, जिससे निरीक्षण कार्यों की मॉनिटरिंग अधिक प्रभावी ढंग से की जा सके।

जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले के सभी ग्रामों में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जल संरचनाओं का सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 30 नल-जल योजनाएं टेस्टिंग अवधि में हैं। इन योजनाओं के सफल संचालन के 15 दिवस पश्चात संबंधित ग्रामों में ÷जल अर्पण दिवस÷ उत्सव के रूप में आयोजित करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही हस्तांतरित की गई 104 जल जीवन मिशन योजनाओं के बंद होने के कारणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

सिकल सेल उन्मूलन अभियान की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिले के 1950 सिकल सेल रोगियों के लिए ÷सिकल मित्र÷ बनाए जाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने स्वयं दो सिकल सेल रोगियों के लिए सिकल मित्र बनने की घोषणा करते हुए अधिकारियों एवं समाज के अन्य वर्गों से भी सिकल मित्र बनने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सिकल मित्र रोगियों के उपचार, पेंशन, सिकल सेल कार्ड निर्माण, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने, स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन तथा विवाह संबंधी परामर्श उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वर्तमान में जिले में 290 सिकल मित्र बनाए जा चुके हैं।

बैठक में कलेक्टर ने जिले के 194 शासन संधारित मंदिरों के प्रबंधन एवं संचालन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) की अध्यक्षता में समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त वनाधिकार प्रकरणों के निराकरण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, विभागीय समन्वय एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की भी विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेन्द्रसिंह चौहान, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर्स एवं अन्य जिला अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

वर्षाकाल में पूरी सतर्कता बरतें अधिकारी, राहत एवं बचाव कार्यों में न हो कोई देरी- कलेक्टर

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष में टीएल बैठक आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने सभी विभागों के समय-सीमा वाले प्रकरणों और सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की और समय सीमा के भीतर सभी प्रकरणों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने वर्षाकाल के दौरान संभावित बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि वर्षा के मौसम में मैदानी अमला मुख्यालय पर रहकर लगातार फील्ड में सक्रिय रहे तथा किसी भी प्रकार की आपदा की सूचना मिलते ही राहत एवं बचाव कार्य तत्काल प्रारंभ किए जाएं। किसी भी स्थिति में लापरवाही या अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।

कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने निर्देश दिए कि बाढ़ संभावित क्षेत्रों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा राहत शिविरों के लिए उपयुक्त भवनों एवं स्थलों का पहले से चयन कर लिया जाए। इन राहत शिविरों में सभी आवश्यक सुविधाओं की अग्रिम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित लोगों को तत्काल सुरक्षित स्थानों पर ठहराया जा सके। उन्होंने कहा कि बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक आपदा से जन-धन की क्षति होने की स्थिति में प्रभावित परिवारों को शासन के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र राहत राशि एवं अन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए।

कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिक्षक एवं अभिभावक बच्चों को नदी, तालाब, झरने तथा जलभराव वाले क्षेत्रों में जाने से रोकें। उन्होंने यह भी कहा कि जर्जर अथवा असुरक्षित आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं स्कूल भवनों में कक्षाओं का संचालन नहीं किया जाए। ऐसे भवनों में संचालित संस्थाओं को आवश्यकता अनुसार सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

बैठक में कलेक्टर ने पशुपालन विभाग को गौशालाओं में वर्षा ऋतु के दौरान गौवंश के लिए चारे, स्वच्छ पेयजल, जल निकासी तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को पेयजल स्रोतों की नियमित जांच कराने तथा जल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए समय-समय पर पानी की टेस्टिंग करने के निर्देश दिए, जिससे वर्षाकाल में जल जनित बीमारियों की रोकथाम की जा सके। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि सभी विभाग वर्षाकाल के दौरान पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य करें और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि जनहानि एवं नुकसान को रोका जा सके। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सर्जना यादव, संयुक्त कलेक्टर सुश्री वंदना राजपूत, श्री रविंद्र परमार, एसडीएम श्री तन्मय वर्मा, श्रीमति स्वाति मिश्रा सहित संबंधित विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।

जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन की खरीदी प्रारंभ

बडवानी/दैनिक मालवा हेराल्ड। ग्रीष्मंकालीन वर्ष 2026 (विपणन वर्ष 2026-27) में न्यूनतम समर्थन मूल्यं योजना अंतर्गत ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केन्द्र पर मूंग की खरीदी जिल में 10 अगस्त तक की जायेगी। जिले में मूंग उपार्जन हेतु 479 किसानों द्वारा 1007 हेक्टर रकबे का पंजीयन किया गया है । जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी हेतु सेंधवा सहकारी विपणन संस्था मर्या. कृषि उपज मंडी सेंधवा एवं खांडेराव मार्केटिंग सहकारी संस्था (ठीकरी) कृषि उपज मंडी अंजड, कुल 02 उपार्जन केन्द्र का निर्धारण किया गया है । अब तक 11 किसानों द्वारा स्लॉट बुकिंग कराया गया है । इस बार मूंग खरीदी में क्यूआर कोड स्केनर एप की नई व्यवस्था लागू की गई, जिसमे किसान की उपज की स्लॉरट बुकिंग मात्रा अनुसार खरीदी की जाकर बिल जनरेट किया जावेगा, फिर बिल संख्या क्यूआर कोड स्केनर एप से स्केन किया जावेगा । जिससे टैग संख्या, तुलाई, बोरो की संख्या के बराबर होगे वही बारदान पर सिलाई होगी, जिससे टैग को स्कैन पर किसान का पूरा बायोडाटा प्रदर्शित होगा।

एकता शिक्षा निकेतन में बाबा साहब के चल समारोह में प्रस्तुति देने वाले बच्चे और अतिथि हुए सम्मानित

खरगोन/ अंजु त्रिवेदी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। खरगोन, रहीमपुरा, संविधान निर्माता, विश्वरत्न बोधिसत्व डॉ.भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित भव्य चल समारोह में एकता शिक्षा निकेतन के बच्चों द्वारा उत्कृष्ट सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं। बच्चों के इस सराहनीय प्रदर्शन और कार्यक्रम में पधारे अतिथियों के सम्मान में स्कूल परिसर में एक विशेष सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के संचालक श्री अनवर पठान द्वारा डॉ. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद, चल समारोह में अपनी कला का शानदार प्रदर्शन करने वाले बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अतिथियों का रहा गरिमामय सानिध्य इस गरिमामय समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रदीप करौंदिया जी उपस्थित रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री नितेश आदित्य जी, श्री उदय कुमार रामटेके जी, हुकुम कोचले जी, दिलीप पंचोली जी, निर्मल पवार जी, पूर्व पार्षद श्रीमती नीला भाई सांवले जी, श्रीमती दुर्गाबाई सवल्दे जी और राजेश खांडे जी शामिल हुए। संस्था द्वारा सभी सम्मानीय अतिथियों का शाल-श्रीफल और स्मृति चिह्न भेंट कर आत्मीय स्वागत व सम्मान किया गया।

वार्डवासियों में दिखा उत्साह- इस अवसर पर स्कूल स्टाफ से, मीरा मैडम, आलिया खान मैडम और नरेंद्र सावल्दे सहित वार्ड क्रमांक 33 रहीमपुरा के गणमान्य नागरिक, बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित रहे। सभी ने बच्चों की प्रतिभा की सराहना की और संस्था के इस प्रयास को सराहा।

यात्री हितों की आवाज को मिले तीन अनुभवी चेहरे, वरिष्ठ पत्रकार, समाजसेवी और अधिवक्ता बने मंच के सलाहकार

सनोलिया, मारू एव साहु को सोपी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी

नागदा/ राजेश सकलेचा/ दैनिक मालवा हेराल्ड। यात्रियों की समस्याओं को मजबूती से उठाने और जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रशासन तक पहुंचाने के उद्देश्य से यात्री विकास एवं सुझाव मंच ने अपने संगठन का विस्तार करते हुए तीन अनुभवी एवं प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों को सलाहकार नियुक्त किया है। वरिष्ठ समाजसेवी राजेश सकलेचा के नेतृत्व में वरिष्ठ पत्रकार कैलाश सनोलिया समाजसेवी पंकज मारू एवं अधिवक्ता एस.के. साहु को मंच का सलाहकार मनोनीत किया गया।

मंच के संकल्प आपका सुझाव, हमारा संकल्प÷ के अनुरूप तीनों नव-नियुक्त सलाहकार अपने-अपने क्षेत्र के अनुभव का लाभ देते हुए यात्रियों की समस्याओं के समाधान, रेलवे सुविधाओं के विस्तार तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को संबंधित विभागों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इस अवसर पर मंच के सस्थापक अध्यक्ष संचालक एवं वरिष्ठ समाजसेवी राजेश सकलेचा ने कहा कि संगठन का उद्देश्य जनभागीदारी के माध्यम से यात्री हितों की रक्षा करना और बेहतर सुविधाओं के लिए सकारात्मक एवं रचनात्मक प्रयास करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि तीनों सलाहकारों के अनुभव से मंच को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी।

नव-नियुक्त सलाहकारों का मंच पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर संयोजक चेतन यादव, सुनील त्रिवेदी भवानी सिंह देवड़ा अध्यक्ष नितिन जैन (उन्हेल) सचिव रवि चौहान (पिपलोदा) कोषाध्यक्ष दीपक जैन, रवि रघुवंशी, योगेश शुक्ला,गौतम लश्करी, जीवनलाल जैन, दिनेश सेठिया, प्रकाश मालपानी, अर्जुन राजोरिया, दिनेश सोलंकी, निलेश जैन सोलंकी, सतीश जैन, सुनील सकलेचा,अनुज नाहर, अमित बम, ध धर्मेन्द्र बम,मनीष भण्डारी, अनिल शर्मा, चन्द्र नारायण शुक्ला, हिमाशु ओझा, भुपेन्द्र चोहान आदि सदस्यो द्वारा शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झाबुआ में एकलव्य योजना अंतर्गत डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु संस्था स्तरीय काउंसिलिंग प्रारंभ

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झाबुआ में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एकलव्य योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों हेतु संचालित तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए संस्था स्तरीय काउंसिलिंग (सीएलसी राउंड) आयोजित की जा रही है।

महाविद्यालय में सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग शाखाओं में उपलब्ध रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं 10वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी संस्था स्तरीय काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए दिनांक 04 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक तकनीकी शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट https://dte.mponline.gov.in पर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।

संस्था स्तरीय काउंसिलिंग के अंतर्गत अभ्यर्थियों को प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रातः 10ः30 बजे से दोपहर 1ः00 बजे तक शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झाबुआ में उपस्थित होना होगा। उपस्थित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी तथा निर्धारित मेरिट के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संपादित की जाएगी।

एकलव्य योजना के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। इनमें निःशुल्क स्टेशनरी एवं ड्राइंग सामग्री, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन व्यवस्था, निःशुल्क परीक्षा सुविधा तथा प्रतिमाह 1000 रुपये की छात्रवृत्ति शामिल है। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा पात्र एवं इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित अवधि में पंजीयन कर संस्था स्तरीय काउंसिलिंग में सहभागिता सुनिश्चित करते हुए तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अपने उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करें।

खरगोन में असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स के अध्यक्ष बने शुभम बगलाने

खरगोन/ अंजु त्रिवेदी/ दैनिक मालवा हेराल्ड। असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए खरगोन जिला इकाई के अध्यक्ष पद पर शुभम बगलाने की नियुक्ति की है। यह नियुक्ति संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष आशुतोष पुरोहित की अनुशंसा पर की गई है। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में कहा गया है कि असेंबली ऑफ एमपी जर्नलिस्ट्स में संगठन और पत्रकार हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। संगठन का प्रत्येक पदाधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करते हुए पत्रकारों के हितों की आवाज़ को प्रभावी ढंग से उठाता है। प्रांतीय अध्यक्ष प्रांतीय अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा ने विश्वास व्यक्त किया कि नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शुभम बगलाने संगठन को जिले में और अधिक सक्रिय एवं मजबूत बनाएंगे तथा पत्रकारों के हितों की रक्षा और संगठन के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

अपनी नियुक्ति पर शुभम बगलाने ने प्रांतीय अध्यक्ष राधावल्लभ शारदा और प्रांतीय उपाध्यक्ष आशुतोष पुरोहित का आभार व्यक्त करते हुए कहॉ की जो विश्वास उन पर किया गया उस पर खरा खतरने का प्रयास करेंगे। संगठन के निर्देशानुसार पत्रकारो के हित और उनकी समास्या को लेकर काम करेंगे। संगठन के पदाधिकारियों एवं पत्रकारों ने शुभम बगलाने को नई जिम्मेदारी मिलने पर वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पुरोहित, शशि शर्मा, राकेश जायसवाल, उमेश रेवलिया, रामेश्वर बडोले, प्रवीण पाल, नरेंद्र भटोरे, ओमप्रकाश रामणेकर, बबलू पाराशर, दिलीप पंचोली, सोनू ठक्कर, कांतिलाल कर्मा, अंकित बड़ोले, अमित भटोरे, श्याम गुप्ता, हरीश कुमरावत, जाकिर खान, कन्हैया कुमरावत, दिनेश सागौर सहित जिले भर के पत्रकार साथियों ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।

सरकार की उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं का जीवंत उदाहरण है इछावर सिविल अस्पताल

सीहोर/ दैनिक मालवा हेराल्ड। सरकार द्वारा नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। सीहोर जिले के इछावर स्थित सिविल अस्पताल आज स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता की एक प्रेरणादायक मिसाल बन चुका है। यह अस्पताल न सिर्फ मरीजों के उपचार का केंद्र है, बल्कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों का भी जीवंत उदाहरण है। यहां प्रतिदिन लगभग 400 मरीज ओपीडी सेवाओं का लाभ लेने आते हैं, जिनमें से 20 से 30 मरीजों को भर्ती किया जाता है। खास बात यह है कि यहां प्रतिदिन औसतन 05 महिलाओं की सुरक्षित डिलीवरी कराई जाती है, जो महिला स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

यह अस्पताल महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान देता है। हर दिन 15 से 20 गर्भवती महिलाओं की एएनसी जांच की जाती है और 03 से 04 महिलाओं का ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक संपन्न होता है। इसके अलावा अस्पताल ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान के लिए भी सक्रिय है, जहां प्रतिदिन 30 से 40 मरीज अपनी जांच करवाने आते हैं। इस अस्पताल में लगभग 80 मरीजों की 200 पैथोलॉजिकल जांच प्रतिदिन की जाती हैं, जो इस अस्पताल की तकनीकी दक्षता और संसाधनों की उपलब्धता को प्रमाणित करता है।

इछावर सिविल अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में भी राज्य में अग्रणी स्थान पर है। इस अस्पताल में प्रतिदिन 8 से 10 नए मरीज इसका लाभ ले रहे हैं। एक्स-रे जैसी सुविधाएं भी यहां निरंतर उपलब्ध हैं, जहां प्रतिदिन 15 से 20 मरीजों का परीक्षण किया जाता है। अस्पताल को उसके समर्पित कार्यों के लिए राज्य सरकार की कायाकल्प योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2020-21 में तीन बार प्रथम पुरस्कार मिल चुका है इन पुरस्कारों के साथ 15 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी गई, जो इसके उत्कृष्ट प्रदर्शन का प्रमाण है।

यह भी गर्व की बात है कि सिविल अस्पताल इछावर को आईएसओ प्रमाणन प्राप्त है और यह लक्ष्य सर्टिफाइड संस्थान भी है, जो प्रसव सेवाओं में मानकों के अनुसार गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। आज यह अस्पताल सिर्फ इलाज का स्थान नहीं है, बल्कि यह विश्वास, सेवा और उत्कृष्टता का प्रतीक बन चुका है। यह सफलता न केवल अस्पताल की मेहनत का परिणाम है, बल्कि सरकार की योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन का भी जीता-जागता उदाहरण है

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से बदली सुशीला रूपसिंह बारिया की जिंदगी

झाबुआ/ दैनिक मालवा हेराल्ड। शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं यदि सही हितग्राहियों तक प्रभावी रूप से पहुंचें और हितग्राही भी परिश्रम एवं लगन के साथ उनका उपयोग करें, तो वे आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम बन सकती हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण झाबुआ जिले के ग्राम सजेली नरसिंहपुरा की अनुसूचित जनजाति वर्ग की हितग्राही श्रीमती सुशीला रूपसिंह बारिया हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के माध्यम से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया है, बल्कि क्षेत्र के अन्य पशुपालकों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं।

मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत श्रीमती सुशीला बारिया को दो उच्च गुणवत्ता वाली मुर्रा नस्ल की भैंसों की एक यूनिट उपलब्ध कराई गई। इस यूनिट की कुल लागत 2 लाख 64 हजार थी, जिस पर शासन द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया गया। योजना के अंतर्गत हितग्राही से केवल 73 हजार का बैंक ड्राफ्ट जमा कराया गया, जबकि शेष राशि का वहन शासन द्वारा किया गया।

योजना की एक विशेष उपलब्धि यह रही कि श्रीमती बारिया को शासन के व्यय पर हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले ले जाया गया, जो मुर्रा नस्ल की भैंसों का प्रमुख एवं मूल प्रजनन क्षेत्र माना जाता है। वहां उन्होंने स्वयं अपनी पसंद से उच्च आनुवंशिक गुणवत्ता वाली दो मुर्रा भैंसों का चयन किया। चयन के उपरांत शासन द्वारा दोनों भैंसों को सुरक्षित रूप से उनके निवास तक पहुंचाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई।

वर्तमान में श्रीमती बारिया की दोनों मुर्रा भैंसों से प्रतिदिन लगभग 17 से 18 लीटर दूध का उत्पादन हो रहा है। उत्पादित दूध का नियमित रूप से ग्राम स्थित सांची दुग्ध संघ के दुग्ध संग्रहण केंद्र पर विक्रय किया जाता है, जिससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 1,080 तथा प्रतिमाह लगभग 30,240 की आय प्राप्त हो रही है। इस नियमित आय ने उनके परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना से प्राप्त सफलता और आर्थिक मजबूती से प्रेरित होकर श्रीमती बारिया ने अपने व्यवसाय का विस्तार करते हुए गुजरात के जूनागढ़ से दो उच्च गुणवत्ता वाली गिर नस्ल की गायों का क्रय किया। वर्तमान में इन गायों से प्रतिदिन लगभग 20 से 25 लीटर दूध का उत्पादन प्राप्त हो रहा है, जिससे उन्हें प्रतिदिन लगभग 1,000 से 1,200 तथा प्रतिमाह लगभग 30,000 की अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है।

वर्षा ऋतु में सुरक्षित पेयजल हेतु किया जा रहा जल स्त्रोतों का क्लोरीनेशन

सीहोर/दैनिक मालवा हेराल्ड। वर्षा ऋतु के दौरान जलजनित बीमारियों रोकथाम के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल स्रोतों का क्लोरीनेशन किया जा रहा है। अभियान के तहत हैंडपंपों, नल-जल योजनाओं तथा अन्य पेयजल स्रोतों में क्लोरीन डाला जा रहा है, ताकि नागरिकों को स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।

विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। इसके लिए विभिन्न स्थानों से जल के नमूने एकत्र कर पेयजल परीक्षण किट के माध्यम से उनकी जांच की जा रही है।

मालिक, प्रकाशक, मुद्रक विजय शर्मा द्वारा 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से प्रकाशित एवं भगवती ऑफसेट 44, बहादुरगंज, उज्जैन (म.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक - विजय शर्मा, मो.नं. 94250-22499, फोन 0734-2553435 प्रधान संपादक : शुभम ताम्रकार (सभी वाद विवाद का न्याय क्षेत्र उज्जैन रहेगा)

12 घंटे में 2 इंच से ज्यादा बारिश, जिले में अब तक 15 इंच से अधिक पानी बरसा

गर्मी और उमस से मिली राहत, सोयाबीन के खेतों में फूटे अंकुर- अगले 3-4 दिन फिर तेज बारिश का अनुमान

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। रविवार शाम से सोमवार सुबह तक हुई दो इंच से अधिक बारिश ने शहर और ग्रामीण क्षेत्रों को तरबतर कर दिया। इस बारिश के साथ ही मौजूदा मानसून सीजन में जिले में अब तक 15 इंच से अधिक वर्षा दर्ज की जा चुकी है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है, वहीं खेतों में बोई गई सोयाबीन की फसल के अंकुर निकलने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं।

रविवार शाम शुरू हुई बारिश देर रात तक जारी रही। तेज बारिश के कारण शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जबकि अनेक प्रमुख सड़कें रात करीब 10 बजे तक जलमग्न रहीं। कई स्थानों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सोमवार सुबह बारिश थमने के बाद मौसम साफ हो गया और धूप निकल आई, लेकिन वातावरण में ठंडक बनी रही। बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में करीब एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई और यह 24 डिग्री पर पहुंच गया। वहीं अधिकतम तापमान लगभग 31 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार को दिनभर गर्मी और उमस से लोग परेशान थे, लेकिन शाम की बारिश ने मौसम को पूरी तरह सुहाना बना दिया। वेधशाला अधीक्षक डॉ. आर.पी. गुप्त के अनुसार उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में अगले तीन से चार दिनों तक अच्छी और कहीं-कहीं तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में प्रशासन ने भी लोगों से मौसम को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की है।

एक नजर में बारिश का असर -रविवार शाम से सोमवार सुबह तक 2 इंच से ज्यादा बारिश।

-मानसून सीजन में अब तक 15 इंच से अधिक वर्षा दर्ज।

-गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली।

-सोयाबीन की फसल के अंकुर निकलने से किसानों में खुशी।

-निचले इलाकों में जलभराव, कई सड़कें देर रात तक पानी में डूबी रहीं।

-अगले 3 से 4 दिन और अच्छी बारिश की संभावना।

पुल-पुलियाओं पर बैरिकेटिंग एवं संकेतक लगाए जाए- कलेक्टर श्री सिंह

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह की अध्यक्षता में आज सोमवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्माण कार्यों, जनसुरक्षा व्यवस्थाओं समायावधि पत्रों, सी.एम हेल्प लाईन एवं विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में वर्षा काल के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश संबंधित विभाग प्रमुखों को दिए गए।

बैठक में निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य से संबंधित सभी विभाग प्रमुख वर्षा ऋ्तु में जनसुरक्षा सुनिश्चित करें तथा किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, इसके लिए आवश्यक सभी सावधानियां समय रहते अपनाई जाएं। वर्षा काल में पुल-पुलियाओं पर बैरिकेडिंग लगाने तथा आवश्यक स्थानों पर पुल-पुलियाओ पर बरसात का पानी होने की स्थिति में पार नहीं करने संबंधि चेतावनी संकेतक लगाने के निर्देश दिए गए।

नगर निगम को निर्देशित किया गया कि रास्तों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तथा किसी भी घटना-दुर्घटना की जानकारी तत्काल संबंधित अधिकारियों को दी जाए ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके।

31 जुलाई तक कराएं "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" अंतर्गत फसलों का बीमा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ-2026 सीजन के लिए फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। किसानों के पास फसल बीमा कराने के लिए अब मात्र 25 दिवस शेष हैं। ऐसे में सभी कृषकों से अपील की गई है कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना समय रहते अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं। किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों से अनुरोध किया गया है कि वे जिस बैंक से उनका किसान क्रेडिट कार्ड बना है, वहां जाकर फसल बुवाई प्रमाण-पत्र एवं पटवारी हल्के की जानकारी अद्यतन कराएं। वहीं अऋ्णी एवं डिफाल्टर कृषकों से भी आग्रह किया गया है कि वे अपने निकटस्थ सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से शीघ्र फसल बीमा कराएं, ताकि योजना का लाभ प्राप्त हो सके।

गंभीर डेम में पानी की आवक शुरू, 257 एमसीएफटी का इजाफा

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। जिले में लगातार हो रही मानसूनी बारिश का सबसे बड़ा असर गंभीर डेम पर दिखाई देने लगा है। महज चार दिनों में डेम में 257 एमसीएफटी पानी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे शहर की पेयजल व्यवस्था को बड़ी राहत मिली है और आने वाले महीनों के लिए जल उपलब्धता की स्थिति मजबूत होने लगी है।

जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 1 जुलाई को गंभीर डेम में 435 एमसीएफटी पानी उपलब्ध था। लगातार बारिश और कैचमेंट क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ने के कारण 5 जुलाई तक यह जल भंडारण बढ़कर 692 एमसीएफटी पहुंच गया। यानी केवल चार दिनों में 257 एमसीएफटी पानी डेम में बढ़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार स्थिति काफी बेहतर है। 5 जुलाई 2025 को गंभीर डेम में केवल 295 एमसीएफटी पानी था, जबकि इस वर्ष इसी तारीख तक जल भंडारण 692 एमसीएफटी पहुंच गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार डेम में दोगुने से भी अधिक पानी संग्रहित हो चुका है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आने वाले दिनों में मानसून इसी तरह सक्रिय रहा और कैचमेंट क्षेत्र में लगातार अच्छी बारिश होती रही, तो गंभीर डेम तेजी से भरने लगेगा। डेम की कुल भंडारण क्षमता 2250 एमसीएफटी है और वर्तमान स्थिति को देखते हुए जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी की संभावना बनी हुई है। लगातार बढ़ते जल भंडारण से शहरवासियों को भविष्य में पेयजल संकट की आशंका काफी हद तक कम होती नजर आ रही है। वहीं किसानों और आम लोगों को भी उम्मीद है कि मानसून का यह दौर आगे भी जारी रहेगा, जिससे जल स्रोतों में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा।

विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम पर जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के उद्देश्य से गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक सोमवार को सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कूमट की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने, जागरूकता कार्यक्रमों, परामर्श व्यवस्था एवं आत्महत्या रोकथाम के प्रयासों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिला स्तरीय निगरानी समिति की सचिव डॉ. वंदना गुप्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि जिले के विभिन्न महाविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यशालाएँ, काउंसलिंग तथा जीवन कौशल आधारित गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। साथ ही शासकीय महाविद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित स्टाफ प्रशिक्षण एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रकोष्ठों का गठन किया गया है तथा उनकी गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है।

सीईओ जिला पंचायत श्री कूमट द्वारा निर्देश दिए गए कि विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, अतः सभी विभागों के मध्य समन्वय स्थापित कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में मानसिक स्वास्थ्य सेल को सक्रिय रखते हुए नियमित जागरूकता कार्यक्रम, काउंसलिंग व्यवस्था तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराई जाए। बैठक में सीएमएचओ डॉ. अशोक पटेल, श्री ब्रजेश त्रिपाठी, श्री सतीश कुमार सोलंकी, डॉ. कविता जैन सहित पुलिस, स्कूल शिक्षा विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी एवं समिति सदस्य उपस्थित रहे।

सस्ता सोना दिलाने के नाम पर धोखा देने वाला आरोपी गिरफ्तार

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। सस्ता सोना दिलाने के नाम पर 9.80 लाख की धोखाधड़ी में शामिल दूसरे आरोपी को पुलिस गुजरात से गिरफ्तार कर उज्जैन लाई है। आरोपी का साथी पूर्व में पकड़ा जा चुका था। फरार दूसरे आरोपी पर 10,000 का इनाम भी घोषित था।

माधव नगर थाना पुलिस ने बताया कि सेठी नगर में रहने वाले अजय यादव ने पिछले महा शिकायत दर्ज कराई थी कि वर्ष 2023 में उसकी पहचान राज उर्फ सुरेश से हुई, जिसने स्वयं को सोना-चांदी का व्यापारी बताते हुए बाजार मूल्य से कम कीमत पर सोना उपलब्ध कराने का झांसा दिया। विश्वास में लेकर आरोपी ने अलग-अलग खातों एवं माध्यमों से बयाना एवं अन्य खर्च के नाम पर राशि प्राप्त की तथा अपने साथी रोहित उर्फ अंकुर जोशी को उज्जैन भेजकर फरियादी से 7.62 लाख नगद भी प्राप्त करवा लिए। इसके बाद दोनों आरोपियों ने अलग-अलग बहाने बनाकर कुल 9.80 लाख की धोखाधड़ी की तथा रुपए वापस मांगने पर फरियादी को झूठे प्रकरण में फंसाने एवं जान से मारने की धमकी देने लगे। मामले में प्रकरण दर्ज कर18 मई को आरोपियों ने पुनः फरियादी को पीजीव्हीटी ग्राउंड, उज्जैन बुलाकर सोना देने का झांसा दिया। फरियादी द्वारा तत्काल थाना माधवनगर पुलिस को सूचना देने पर पुलिस ने योजनाबद्ध कार्रवाई करते हुए आरोपी रोहित उर्फ अंकुर जोशी को मौके से गिरफ्तार किया था, जबकि मुख्य आरोपी सुरेश उर्फ राज मौके से फरार हो गया था। जिसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। जिसकी गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम गठित की गई थी। रविवार को एक टीम गुजरात के जिला पाटन रवाना की गई। जहां से फरार इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर सोमवार दोपहर उज्जैन लाया गया। आरोपी सुरेश उर्फ राज पिता कांतिलाल जोशी, 45 वर्ष, निवासी ग्राम दादका, जिला पाटन (गुजरात) ने पूछताछ में धोखाधड़ी करना स्वीकार किया है। जिसके पास से 20,000 नगद करामात भी किए गए हैं।

कलेक्टर श्री सिंह द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह द्वारा जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को जिले में एक पेड़ मां के नाम अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। अभियान को पूर्ण उत्साह के साथ भव्य स्तर पर सफल बनाने के निर्देश दिए गए है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के जल एवं सामुदायिक सहयोग से यह राष्ट्रव्यापी अभियान वर्ष 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस (05 जून 2024) को एक पौधा रोपित कर प्रारंभ किया गया था। इस वर्ष यह अभियान 05 जून 2026 से 30 सितंबर 2026 तक पूरे प्रदेश एवं देशभर में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है।

अभियान के मुख्य बिंदु- मुख्य क्रियान्वयन माध्यम- अभियान को मुख्य रूप से स्कूलों के माध्यम से मिशन स्ङ्कस्नश्व के अंतर्गत इको क्लब्स की देखरेख में संचालित किया जाएगा। इस दौरान कॉलेजों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को भी सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। रोपण कार्य स्थानीय मौसम के अनुरूप किया जाएगा।

सीहोर से था फरार घटिया थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। पास्को एक्ट में आष्टा से फरार चल रहे आरोपी की सूचना घट्टिया थाना एसआई को मिली तो निपानिया टोल पर नाकाबंदी की गई। आरोपी दोस्त के साथ कार में सवार मिला। जिसे हिरासत में लेकर शनिवार-रविवार रात 2 बजे सिहोर पुलिस को सौंपा। आरोपी पर 10 हजार का इनाम घोषित था।

घट्टिया थाना प्रभारी करण खोवाल ने बताया कि रात को चैकिंग के दौरान एसआई प्रवेश जाटव को सिहोर में पदस्थ बैचमेट से सूचना मिली थी कि आष्टा से पास्को एक्ट के मामले में सालभर से फरार चल रहे आरोपी पिंटू उर्फ अरविंद 22 वर्ष, निवासी भवरा थाना आष्टा के घट्टिया क्षेत्र से गुजरने की खबर मिली है। जिसे गिरफ्तार करना है। एसआई जाटव ने टीम के साथ निपानिया टोल पर नाकाबंदी की। कुछ देर में ही उक्त आरोपी कार में सवार होकर टोल पर पहुंचा, उसे टोल पार करने से पहले ही दबोचा गया और थाने लाया गया। पूछताछ करने पर सामने आया कि फरार आरोपी का परिवार भी पीछे आयशर में सवार होकर आ रहा है। सभी राघवी में रिश्तेदार के यहां आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। फरार आरोपी के गिरफ्त में आने पर आष्टा सिहोर पुलिस को अवगत कराया गया। रात 2 बजे आष्टा पुलिस घट्टिया पहुंची और आरोपी को अपने साथ लेकर रवाना हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी के खिलाफ 10 हजार का इनाम भी घोषित था।

मूक-बधिर युवती से छेड़छाड़ करने वाला हिरासत में

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मूक-बधिर और मानसिक रूप से विक्षिप्त युवती के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद 1 घंटे में हिरासत में ले लिया। विक्षिप्त युवती के भाई की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

भाटपचलाना थाना पुलिस ने बताया कि सुनील पिता मुन्नालाल, निवासी ग्राम बालोदा लखखा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 21 वर्षीय बहन घर में अकेली सो रही थी। इसी दौरान ग्राम बालोदा लखखा निवासी मांगीलाल पिता बगदीराम अनाधिकृत रूप से घर में घुस आया तथा बहन के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बहन के विचलित होने की आहट आने आने पर उसके कमरे में पहुंचे तो मांगीलाल भाग निकला। भाई ने बताया कि उसकी बहन मूक-बधिर होकर मानसिक रूप से विक्षिप्त है। पुलिस ने युवती के भाई की शिकायत पर धारा 333, 75(1) बी.एन.एस. का प्रकरण दर्ज किया और आरोपी की तलाश शुरू की 1 घंटे में ही उसे हिरासत में ले लिया गया। जिसे न्यायालय में पेश कर जेल भेजा गया है।

इस बार गजकेसरी योग में शुरू होगी गुप्त नवरात्रि

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। पंचांग के अनुसार इस वर्ष 15 जुलाई से आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्र का शुभारंभ अत्यंत मंगलकारी योग में होगा। खास बात यह है कि इस बार गुप्त नवरात्र की शुरुआत गजकेसरी योग और बुध-पुष्य नक्षत्र की शुभ साक्षी में होगी।

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग कई वर्षों बाद बन रहा है, जिससे देवी साधना, पूजा-अर्चना और शुभ कार्यों का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा।ज्योतिषाचार्य पं. अमर डब्बावाला के अनुसार प्रतिपदा तिथि पर पुष्य नक्षत्र, ब्रज योग, बव करण तथा कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति मिलकर गजकेसरी योग का निर्माण करेगी। तिथि, वार, नक्षत्र और योग का यह मेल साधकों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन देवी की आराधना शुरू करने से मनोकामनाओं की पूर्ति और विशेष पुण्यफल प्राप्त होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार वर्ष में चार नवरात्र आते हैं। इनमें माघ और आषाढ़ के नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाते हैं, जबकि चैत्र और शारदीय नवरात्र सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं। गुप्त नवरात्र में विशेष रूप से तंत्र, मंत्र, यंत्र साधना के साथ देवी उपासना का महत्व बताया गया है। इस बार गुप्त नवरात्र के दौरान बनने वाले शुभ योगों को नई शुरुआत, आध्यात्मिक साधना और विशेष अनुष्ठानों के लिए भी अत्यंत फलदायी माना जा रहा है।

नए बन रहे घाटों के एप्रोच रोड भी होंगे हरे- भरे

नगर निगम हर पौधे की जियो-टैगिंग कर करेगी निगरानी

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। आगामी सिंहस्थ को हरित और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए नगर निगम ने व्यापक पौधारोपण की तैयारी शुरू कर दी है। निर्माण कार्य पूरे हो चुके घाटों और उनकी एप्रोच सड़कों पर छायादार पौधे लगाए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को आवागमन के दौरान पर्याप्त छाया मिल सके। यह अभियान अमृत हरित महाअभियान के तहत चलाया जाएगा, जिसमें जिले में 10 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

नगर निगम अपरायुक्त पवन कुमार सिंह के अनुसार, शिप्रा नदी के निर्माणाधीन 29.2 किलोमीटर लंबे घाटों में जहां-जहां निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, वहां प्राथमिकता से पौधारोपण किया जाएगा। इसके साथ ही घाटों तक पहुंचने वाली सड़कों को भी हरित बनाने की योजना तैयार की गई है। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण के लिए गड्ढे खोदने का कार्य भी तेजी से चल रहा है। बैठक में अधिकारियों ने सिंहस्थ क्षेत्र के अलावा नानाखेड़ा परिसर, एमआर-5, डंपर स्टैंड, खेल परिसर, प्रमुख उद्यान, सरकारी संस्थान, अस्पताल, कॉलेज, गोशालाएं, काल भैरव क्षेत्र, ट्रेंचिंग ग्राउंड और अन्य सार्वजनिक स्थलों को भी पौधारोपण के लिए चिन्हित किया। वहीं सिंहस्थ क्षेत्र की करीब 114 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर 8 से 10 फीट ऊंचे छायादार पौधे लगाए जाएंगे। नगर निगम ने पौधारोपण के साथ उनकी सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया है। प्रत्येक पौधे की जियो-टैगिंग की जाएगी, ताकि उसकी नियमित निगरानी और देखभाल सुनिश्चित हो सके। अभियान में नगर निगम के साथ विभिन्न शासकीय विभाग, सामाजिक संगठन, पर्यावरण प्रेमी, वृक्ष मित्र और आम नागरिकों की भी भागीदारी रहेगी।

बैठक में यह मुद्दा भी सामने आया कि सेवाद क्षेत्र में वर्षों पहले लगाए गए बांस के बड़े हिस्से को घाट निर्माण के दौरान हटा दिया गया, लेकिन अब तक उसका समुचित संरक्षण या स्थानांतरण नहीं किया गया। अधिकारियों ने भविष्य में हरित क्षेत्र के संरक्षण और पौधों की बेहतर देखभाल पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

बाइक सवार पर गिरा हाईटेंशन लाइन का तार

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। पेट्रोल पंप से बाइक में पेट्रोल भरवा कर निकले बाइक सवार तीन युवकों पर बिजली की हाई टेंशन लाइन का तार टूट कर गिर गया। दो युवकों ने खुद की जान बचा ली लेकिन बाइक चलाने वाले की मौत हो गई। मामला हरिफाटक बच के पास का होना सामने आया है।

नीलगंगा थाना पुलिस ने बताया कि रात में बारिश के बीच हरिफाटक ब्रिज के पास शिप्रा ढाबे के सामने बाइक सवार पर हाई टेंशन लाइन का तार टूट कर गिर गया था। करंट लगने पर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। बारिश के चलते और तार में करंट होने से आसपास फैल रहा था। बिजली विभाग को सूचना देकर क्षेत्र की बिजली व्यवस्था को बंद कराया गया उसके बाद युवक को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर बॉडी को पोस्टमार्टम कक्ष में रखा। मामले में मर्ग कायम कर सोमवार सुबह पोस्टमार्टम कराया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक का नाम आशिक उर्फ छोटू पिता अहमद नूर निवासी तालोद रहने वाला था। उसके साथ बाइक पर सवार दो युवक भतीजे थे। तीनों मजदूरी कर अपने घर लौट रहे थे। हरि फाटक ब्रिज के पास गोल्डन पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरने पहुंचे थे। जहां से वह ग्राम तालोद के लिए निकले थे इस दौरान घटना हुई है। हादसा सामने आने के बाद कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने परिवार को चार लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है।

महाकाल के दरबार पहुंचे दो कैबिनेट मंत्री, किए दर्शन

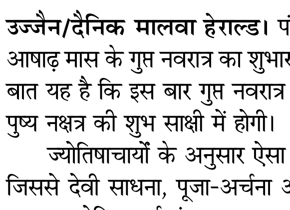

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल तथा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्तिया उइके ने सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मंदिर में विधिवत दर्शन-पूजन किया। वहीं मंत्री संपत्तिया उइके ने प्रातःकालीन भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोनों मंत्रियों का महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक ने स्वागत किया।

ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव...400 पुलिसकर्मियों को शहर के 8 जोन में किया तैनात

सिंहस्थ प्रशिक्षण के तहत आए 250 अतिरिक्त जवानों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की दी जा रही ट्रेनिंग

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। शहर में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़ और यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी तरह नए ढंग से संचालित करने की तैयारी कर ली है। अब शहर की सड़कों पर 400 पुलिसकर्मी यातायात व्यवस्था संभालते नजर आएंगे। इसके लिए पूरे शहर को आठ जोन में विभाजित किया गया है। हर जोन की जिम्मेदारी अलग-अलग अधिकारियों और पुलिस बल को सौंपी गई है, ताकि किसी भी क्षेत्र में जाम की स्थिति बनने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

उज्जैन पुलिस को सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत लगभग 250 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों का बल मिला है। पहले से कार्यरत करीब 150 यातायात पुलिसकर्मियों को मिलाकर अब कुल 400 जवान ट्रैफिक प्रबंधन में तैनात रहेंगे। चूंकि अतिरिक्त बल अन्य जिलों से आया है, इसलिए उन्हें शहर की भौगोलिक स्थिति, प्रमुख मार्गों, वीआईपी रूट, डायवर्जन प्लान और संवेदनशील चौराहों की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। जवानों को उन स्थानों की भी जानकारी दी जा रही है, जहां नियमित रूप से सबसे अधिक ट्रैफिक दबाव रहता है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। यदि कहीं जाम की स्थिति बनती है तो संबंधित जोन का पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचकर यातायात सामान्य करेगा। प्रशासन का उद्देश्य आगामी धार्मिक आयोजनों और बढ़ती आवाजाही के बीच ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है।

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई- यातायात पुलिस अब नियमों के पालन को लेकर भी सख्त रुख अपनाएगी। जिन चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, वहां रेड और ग्रीन लाइट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही से वाहन चलाने और नियम तोड़ने वाले चालकों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

ई-चालान नहीं भरा तो निजी एजेंसी करेगी वसूली- उधर, ई-चालान की राशि जमा नहीं करने वाले वाहन चालकों पर भी अब शिकंजा कसने की तैयारी है। उज्जैन स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बकाया चालान की वसूली के लिए निजी एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसके लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं और इच्छुक कंपनियों से 15 दिनों के भीतर आवेदन मांगे गए हैं।

नई व्यवस्था के तहत एजेंसी प्रत्येक बकायादार वाहन मालिक से कम से कम तीन बार संपर्क करेगी। फोन कॉल, व्हाट्सएप, ई-मेल और घर पहुंचकर चालान जमा कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ऑनलाइन भुगतान के लिए लिंक भी उपलब्ध कराया जाएगा। हर कॉल और घर-घर संपर्क का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा।

प्रारंभिक रूप से यह अनुबंध तीन वर्षों के लिए होगा। बेहतर प्रदर्शन की स्थिति में अवधि बढ़ाई जा सकेगी। एजेंसी को टेलीकॉलर, फील्ड एग्जीक्यूटिव और प्रोजेक्ट मैनेजर की टीम तैनात करनी होगी तथा हर महीने न्यूनतम 12 लाख रुपए की बकाया राशि वसूलने का लक्ष्य पूरा करना होगा। पुलिस और प्रशासन का मानना है कि अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, आठ जोन की नई व्यवस्था और ई-चालान वसूली की सख्त प्रणाली से शहर की यातायात व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और अनुशासित हो सकेगी।

आकाश पेट्रोल पंप के सामने नाले में मिली युवक की लाश

उज्जैन/दैनिक मालवा हेराल्ड। आगर रोड आकाश पेट्रोल पंप के सामने नल से सोमवार सुबह एक युवक की लाश बरामद की गई है। जिसकी पहचान के प्रयास किया जा रहे हैं। चिमनगंज थाना पुलिस ने बताया कि सुबह कुछ लोगों द्वारा पेट्रोल पंप के सामने नाले में लाश पड़ी होने की सूचना दी गई थी। पुलिस के पहुंचने पर आसपास के लोगों की मदद से युवक को नाले से बाहर निकाला गया। आसपास के लोगों से पहचान के प्रयास किया लेकिन किसी ने भी उसकी शिनाख्त नहीं की। युवक की जानकारी एकत्रित करने के लिए उसके कपड़ों की तलाशी ली गई उसके पास से एक तंबाकू की पुड़िया और देसी शराब का लाल क्वार्टर मिला। पहचान का कोई दस्तावेज नहीं था। मृतक ने काले रंग का लोअर और मेहरून रंग की टी-शर्ट पहन रखी थी। शव को पोस्टमार्टम कक्ष पहुंचाया गया है और मामले में मर्ग कायम किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि रात को हुई बारिश के दौरान युवक शराब के नशे में नाले में गिरा है जिसके चलते उसकी डूबने से मौत हुई है। पहचान होने पर ही युवक के संबंध में जानकारी सामने आ पाएगी। एसआई सुरेंद्र मंडलोई ने बताया कि मृतक की पहचान के लिए जिले के थाना पुलिस को फोटो भेजे गए हैं और गुमशुदा लोगों की जानकारी मांगी गई है।